लखनऊ

गुरुवार, 21 मई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 265

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए.. विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता हि है...!

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi | NIGHT 29° Low

संक्षेप

महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; सिख धार्मिक संपत्तियों पर PIL सुनने से इनकार

नई दिल्ली। महिला वकीलों को सरकारी कानूनी पैनलों और लॉ ऑफिसर पदों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत को बताया कि महिला वकीलों की स्थिति पर SCBA के सर्वे के बाद यह याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि महिलाओं की कानून की पढ़ाई में भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी पैनलों और उच्च पदों पर उनकी हिस्सेदारी बेहद कम है। याचिका के अनुसार, स्वतंत्रता के 75 वर्षों में अब तक कोई महिला अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल नहीं बनी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या लगभग 5.88 प्रतिशत और हाई कोर्ट में 13.76 प्रतिशत है। याचिका में केंद्र, राज्यों और पीएसयू को निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी सरकारी कानूनी पैनलों में महिलाओं को कम से कम 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

मेटा ने पहले दिया 'वर्क फ्रॉम होम', फिर तड़के सुबह 8 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

नई दिल्ली, एजेंसी। मेटा में एक बार फिर छंटनी का दौर शुरू हो गया है। इस बार कंपनी का तरीका थोड़ा अलग और हैरान करने वाला रहा। कर्मचारियों को पहले घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने का निर्देश मिला और फिर सुबह-सुबह नौकरी जाने के ईमेल आने लगे। मेटा में इस बार की छंटनी बेहद शांति और सावधानी के साथ अंजाम दी गई। कंपनी ने अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के अपने ऑफिसों में कर्मचारियों को अचानक निर्देश दिया कि वे उस दिन घर से ही काम (वर्क फ्रॉम होम) करें। इस फैसले के पीछे कंपनी का मकसद स्पष्ट था, ऑफिस के गलियारों में किसी भी तरह की हलचल, शोर या विरोध से बचना। जब कर्मचारी घरों में थे, तभी अचानक छंटनी के ईमेल आने शुरू हो गए। मेटा अपनी कुल वर्कफोर्स का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 8 हजार कर्मचारियों को बाहर कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रक्रिया की शुरुआत सिंगापुर के ऑफिस से हुई। यहां प्रभावित कर्मचारियों को स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे (भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे) नौकरी से निकाले जाने के ईमेल मिले। अब कंपनी दुनिया भर में अपने अलग-अलग टाइम जोन के हिसाब से इसी तरह से सूचनाएं भेज रही है। मेटा में हो रहे इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य कारण कंपनी की नई प्राथमिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) है। पहले लगभग 78 हजार कर्मचारियों वाली इस कंपनी में अब न केवल हजारों लोगों की छंटनी की जा रही है, बल्कि हजारों अन्य कर्मचारियों का रोल भी बदला जा रहा है। मेटा की चीफ पीपल ऑफिसर जेनेल गेल ने एक इंटरनल मेमो के जरिए बताया कि कंपनी का पूरा जोर अब नई एआई-नेटिव टीमों को तैयार करने पर है।

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्टों की हड़ताल का मिला-जुला असर

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय रसायनज्ञ और औषधि विक्रेता संगठन (एआईओसीडी) की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का देश के विभिन्न हिस्सों में मिला-जुला असर देखने को मिला। अधिकांश जगहों पर केमिस्ट दुकानें बंद रहीं, जबकि अस्पतालों के आसपास कुछ दुकानें खुली भी नजर आईं। तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में 1,100 मेडिकल दुकानें पूरी तरह बंद रहीं।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में करीब 850 थोक और खुदरा दुकानें हड़ताल से प्रभावित हुईं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी ज्यादातर केमिस्टों ने दुकानें बंद रखीं।हड़ताल का समर्थन करते हुए एक केमिस्ट ने कहा, "हम ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण नहीं रह जाता और नकली दवाओं का खतरा बढ़ जाता है।"

हालांकि, कुछ इलाकों में केमिस्टों ने मरीजों की सुविधा को देखते हुए दुकानें खोल रखीं। दिल्ली के एक केमिस्ट ने बताया, "हमारी दुकान अस्पताल के ठीक बाहर है। दूर-दूर से मरीज आते हैं। अगर दुकान बंद रहेगी तो उन्हें परेशानी होगी, इसलिए हमने दुकान खुली रखी है।"

ग्राहक बोले- ऑनलाइन ज्यादा फायदेमंद

दूसरी ओर, आम ग्राहक ऑनलाइन दवा खरीदारी के पक्ष में नजर आए। एक ग्राहक ने कहा, "ऑनलाइन दवा सस्ती पड़ती है, छूट भी मिलती है और घर बैठे समय पर डिलीवरी हो जाती है। कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता। आपात स्थिति में ऑफलाइन ले लेंगे, लेकिन रोजमर्रा के लिए ऑनलाइन विकल्प ज्यादा बेहतर है।"

मोदी-शाह पर राहुल का विवादित बयान, भाजपा का पलटवार- 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री को 'गद्दार' कहा। रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वीरा पासी जी, अंबेडकर जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में हर नागरिक एक समान है। सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उनकी सोच अर्बन नक्सल जैसी है। राहुल ने कहा कि ये देश सबका है, किसी एक जाति या संगठन का नहीं है। यही बात देश का संविधान भी कहता है। संविधान में हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है। संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया।

राहुल की सोच अर्बन नक्सल जैसी: भाजपा

राहुल ने इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों को 'गद्दार' कहा। राहुल की मानसिकता नक्सलियों जैसी है। उनकी सोच अर्बन नक्सल जैसी है। राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं।

राहुल ने पीएम मोदी-अमित शाह को 'गद्दार' कहा

राहुल ने आगे कहा कि जब भी BJP-RSS के लोग आपके सामने आएं और नरेंद्र मोदी-अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए "नरेंद्र मोदी-अमित शाह गद्दार हैं। BJP-RSS गद्दार हैं", क्योंकि आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। बीजेपी और आरएसएस ने संविधान पर, वीरा पासी जी, गांधी जी और अंबेडकर जी पर हमला किया है।

'देश में आर्थिक तूफान आने वाला है'

राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता से सोना नहीं खरीदने, विदेश नहीं जाने, इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलने को कहते हैं। ये सब कहने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी हजारों-करोड़ के जहाज में बैठकर विदेश चले जाते हैं और जनता चुपचाप देखती रहती है जबकि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। भीषण महंगाई होगी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे और खाद की कमी हो जाएगी।

यह नीतिगत मामला, हम दखल नहीं दे सकते... सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जातिगत जनगणना नीतिगत मामला है। इसमें हम दखल नहीं दे सकते। CJI सूर्यकांत ने कहा कि जनगणना जातिगत हो या ना हो, यह सरकार का फैसला है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को ओबीसी की संख्या पता होनी चाहिए। सरकार को यह जानना होगा कि पिछड़े वर्ग में कितने लोग हैं। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कास्ट डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। सरकार के पास पहले से ही काफी आंकड़े हैं, इसलिए नई जाति गणना की कोई जरूरत नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि देश में कितने लोग पिछड़े वर्ग के हैं, ताकि उनके लिए सही योजनाएं बनाई जा सकें। उन्होंने कहा कि कोर्ट सरकार के इन नीतिगत फैसलों में तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक वे कानून के खिलाफ न हों। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

छह महीने तक चलेगा पहला चरण

जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने-अपने क्षेत्र में 30 दिनों के भीतर सर्वेक्षण पूरा करना होगा। विशेष बात यह है कि पहली बार घर-घर सर्वेक्षण करने से पहले 15 दिन की स्व-गणना कराने का समय दिया गया है, जिससे कि देश का कोई भी सामान्य नागरिक अपनी सुविधा अनुसार पहले ही जानकारी दर्ज कर सकें। बता दें कि यह देश की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना है, जिसे लोग स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से भी भर सकेंगे।

जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू

भारत में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। कोविड के कारण पांच साल की देरी के बाद, यह जनगणना दो चरणों में डिजिटल माध्यम से की जा रही है। हाउस लिस्टिंग और घरों की गणना 16 अप्रैल से 15 मई तक चली। पहले चरण में घर-संपत्ति की जानकारी ली गई जबकि दूसरे चरण में परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण 2027 से शुरू होगा। जनगणना के पहले चरण की शुरुआत फिलहाल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। इनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और दिल्ली के एनडीएमसी व दिल्ली कैंट क्षेत्र शामिल हैं।

हाईकोर्ट का अहम फैसला, गंभीर अपराधों के आरोपियों को पुलिस में नौकरी नहीं, भले ही दोषसिद्धि न हुई हो

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि गंभीर अपराधों के मामलों में आरोपी व्यक्ति को पुलिस जैसे अनुशासित बल में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा कि पुलिस विभाग सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और कानून-व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील सेवा है। न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की एकल पीठ ने यह फैसला शेखर नाम के एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज करते हुए पारित किया। याची का तर्क था कि उसके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमा दुर्भावना से प्रेरित है और अभी तक उसकी दोषसिद्धि नहीं हुई है, इसलिए उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दोषसिद्धि न होना किसी अभ्यर्थी को स्वतः नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। पुलिस जैसी अनुशासित सेवा में चयन के लिए अभ्यर्थी का निष्कलंक चरित्र आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के आपराधिक आरोप लंबित हैं तो सक्षम प्राधिकारी उसके आचरण और पृष्ठभूमि का मूल्यांकन कर उसे नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त मान सकता है। न्यायालय ने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं, विशेषकर पुलिस बल में नियुक्ति के मामलों में चरित्र सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में राज्य को यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तियों को सेवा में प्रवेश से रोके जिनकी पृष्ठभूमि से विभाग की साख और अनुशासन प्रभावित होने की संभावना हो।

शरद पवार की बैठक से नदारद रहे रोहित, नाराजगी की खबरों को बताया अफवाह

मुंबई, एजेंसी। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करना और पार्टी के पुनरुद्धार के लिए मजबूत रणनीतियां तैयार करना था। दक्षिण मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में आयोजित इस बैठक में एनसीपी के सांसदों, विधायकों और 2024 के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बैठक में आगामी 10 जून को होने वाले पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों पर भी गहन मंथन हुआ। इस अहम बैठक से शरद पवार के प्रपौत्र और पार्टी विधायक रोहित पवार नदारद रहे। उनके इस कदम से सियासी गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि, रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने साफ कहा कि उनके नाराज होने की खबरें अफवाह मात्र हैं और वे सभी पवार साहब के मार्गदर्शन में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। रोहित पवार ने बैठक में न आने की वजह बताते हुए कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र कर्जत-जामखेड अहिल्यानगर जिला के कुकडी क्षेत्र और बारामती में जनई-शिरसाई परियोजना से किसानों को मिलने वाले पानी का मुद्दा बेहद गंभीर हो गया था। इसी वजह से उन्हें अचानक पुणे के सिंचाई भवन जाना पड़ा। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अधिकारियों पर दबाव न होता और उन्होंने पानी छोड़ने का अपना वादा निभाया होता, तो वे पुणे जाने के बजाय मुंबई की पूर्व-निर्धारित बैठक में शामिल हो सकते थे।

मोदी-शाह पर राहुल का विवादित बयान

उत्तर बंगाल को सीएम सुवेंदु की सौगात, एम्स-आईआईटी और कैंसर अस्पताल का किया बड़ा ऐलान

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि उत्तर बंगाल ने लगातार भाजपा का समर्थन किया है और उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र के वादों को दोहराया, जिनमें इस क्षेत्र में एम्स, आईआईटी और कैंसर अस्पताल की स्थापना शामिल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार उत्तर बंगाल पहुंचे और कहा कि उनकी सरकार विकास योजनाओं की नियमित निगरानी और लोगों से बातचीत के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी।

बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने

कहा, 'उत्तर बंगाल ने बार-बार भाजपा का साथ दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत किया है। उत्तर बंगाल में काम करके हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।' उन्होंने आगे घोषणा की कि इस क्षेत्र के भाजपा मंत्री नागरिकों से सीधे जुड़ने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए साप्ताहिक जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

अधिकारी ने कहा कि उत्तर बंगाल के हमारे मंत्री सप्ताह में एक बार 'जनता दर्शन' आयोजित करेंगे; प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए, वे चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और नियमित बैठकों के माध्यम से पूरे उत्तर बंगाल क्षेत्र में हर योजना के कार्यान्वयन की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि हम अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करेंगे, जिनमें उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और कैंसर अस्पताल की स्थापना शामिल है। इससे पहले दिन में, भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि उत्तर बंगाल को पिछली सरकारों के तहत लंबे समय से भेदभाव का सामना करना पड़ा है और अब भाजपा नेतृत्व में इसका नया विकास होगा।

बिस्टा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार सिलीगुड़ी का दौरा कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने हमेशा उत्तर बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया है; उत्तर बंगाल को भेदभाव का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर बंगाल अपनी गरिमा वापस हासिल करेगा और विकास भी देखेगा," । उन्होंने यह भी दावा किया कि यह क्षेत्र "टीएमसी के कुशासन से मुक्त हो चुका है।

चीन-पाक की खैर नहीं! रूस ने भारत को दिया Su-57 स्टील्थ फाइटर और खतरनाक R-77M मिसाइल का ऑफर

नई दिल्ली, एजेंसी। रूस ने भारत को अपने पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रस्ताव दिया है। इस बार मॉस्को ने सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि उसके साथ अगली पीढ़ी की R-77M एयर-टू-एयर मिसाइल भी ऑफर की है, जिसे चीन और पाकिस्तान के बढ़ते स्टील्थ खतरे का जवाब माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, रूस ने भारतीय वायुसेना के लिए 40 से 60 Su-57 फाइटर जेट सीधे तैयार हालत में देने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद भारत में कम से कम 100 अतिरिक्त विमानों का लाइसेंस उत्पादन करने की योजना भी शामिल है। यह पूरा प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' और घरेलू रक्षा उत्पादन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

हाल ही में रूस ने Su-57 का दो-सीटर वर्जन Su-57D भी पेश किया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक, यह भारतीय वायुसेना की जरूरतों के ज्यादा करीब माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से दो सीट वाले लड़ाकू विमानों को जटिल मिशनों और ड्रोन-टीमिंग ऑपरेशन के लिए बेहतर मानता रहा है। रूस का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब चीन तेजी से अपने J-20 स्टील्थ फाइटर बेड़े को बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान भी भविष्य में स्टील्थ लड़ाकू विमान हासिल करने की तैयारी में माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक Su-57E भारत के लिए एक 'इंटरिम स्टील्थ प्लेटफॉर्म' बन सकता है, जब तक कि भारत का स्वदेशी AMCA फाइटर 2030 के दशक में सेवा में नहीं आ जाता।

खतरनाक R-77M मिसाइल की क्या खासियत?

R-77M BVRAAM मिसाइल खास तौर पर Su-57 के लिए विकसित की गई है और इसे विमान के अंदरूनी वेपन बे में रखा जा सकता है, जिससे फाइटर की स्टील्थ क्षमता बनी रहती है।

R-77M की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसमें डुअल-पल्स रॉकेट मोटर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

इसका पहला इंजन मिसाइल को ऊंचाई तक तेज गति से पहुंचाता है, जबकि दूसरा इंजन अंतिम चरण में सक्रिय होकर लक्ष्य के पास मिसाइल की गति और Maneuverability को बनाए रखता है।

यह तकनीक दुश्मन के अत्यधिक फुर्तीले लड़ाकू विमानों को भी लंबी दूरी पर मार गिराने में सक्षम बनाती है। इससे मिसाइल का 'नो-एस्केप जोन' काफी बड़ा हो जाता है, यानी लक्ष्य के बच निकलने की संभावना बेहद कम हो जाती है।

आंसर शीट के लिए दर-दर भटक रहे सीबीएसई के छात्र, वेबसाइट हुई ठप

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया, जब मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल अचानक ठप हो गया। बोर्ड ने 19 मई 2026 से छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन वेबसाइट के काम न करने से परेशान छात्रों ने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली और भारी बवाल खड़ा कर दिया।

छात्रों की लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सीबीएसई को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। स्थिति को स्पष्ट करते हुए बोर्ड ने एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है।

इस सर्कुलर में सीबीएसई ने खुद यह बात स्वीकार की है कि कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की हुई कॉपियां प्राप्त करने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण छात्रों को आवेदन करने में बाधा का सामना करना पड़ रहा है।

आज दोपहर 2 बजे से फिर शुरू होगा पोर्टल, बोर्ड ने की ये अपील

इस परेशानी से जूझ रहे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बोर्ड ने बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम इस सर्वर की समस्या को सुलझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सीबीएसई के सर्कुलर में जानकारी दी गई है कि पूरी उम्मीद है कि आज (20 मई) दोपहर 2 बजे तक यह वेबसाइट फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। बोर्ड ने इस संबंध में छात्रों और अभिभावकों से धैर्य और सहयोग का अनुरोध किया है। साथ ही छात्रों से यह भी अपील की गई है कि जैसे ही आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू हो, वे बिना किसी देरी के जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ उठाएं।

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नीति पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिवों को किया तलब, कहा- 9 साल बाद भी नहीं बनी स्थायी पुनर्वास नीति

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास और सहायता व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने गृह विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों को 25 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

यह आदेश एक एसिड अटैक पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। जिसमें पीड़िता ने राज्य की ओर से पुनर्वास और दीर्घकालिक सहायता की मांग की थी। अदालत ने कहा कि घटना के

नौ साल बाद भी राज्य सरकार पीड़ितों के लिए व्यापक सहायता प्रणाली तैयार करने में विफल रही है।

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से चिकित्सा उपचार, पुनर्निर्माण सर्जरी, काउंसलिंग, शिक्षा और रोजगार सहायता के लिए ठोस व्यवस्था का खाका पेश करने को कहा है। अदालत ने सरकार की केवल एकमुश्त आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।

एसिड अटैक पीड़ितों की जिंदगी पर असर

कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों की जिंदगी पर आजीवन असर पड़ता है। इसलिए मामूली और अस्थायी मुआवजे के बजाय उन्हें दीर्घकालिक और संरचनात्मक सहायता की जरूरत है।

हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को चोट की गंभीरता और उसके जीवनभर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह तय और संतुलित किया जाएगा।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कई अवसर और पूर्व आदेशों में उठाए गए सवालों के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि एसिड अटैक पीड़ितों के लिए व्यापक नीति क्यों नहीं बनाई गई। कोर्ट ने कहा कि अब इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे विचार-विमर्श की जरूरत है ताकि नीति निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर जल्द प्रभावी व्यवस्था लागू की जा सके।

शिक्षा विभाग का बड़ा खेल बेनकाब

सुल्तानपुर। बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए गए शिक्षकों के आदेश को हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद आनन-फानन में प्रत्यावर्तित करना पड़ा। इस पूरे मामले ने विभागीय पारदर्शिता और वरिष्ठता नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर सिंह, पूर्व जिला प्रवक्ता राहुल राष्ट्रवादी समेत कई शिक्षकों ने आदेश वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पूरी तरह वरिष्ठता सूची के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि बीएसए सार्वजनिक रूप से वरिष्ठता सूची जारी करें और निष्पक्ष तैनाती सुनिश्चित करें। सूत्रों के हवाले से बड़ा आरोप है कि बीएसए के करीबी बताए जा रहे पंकज सिंह को वरिष्ठता सूची दरकिनार कर प्रभारी प्रधानाध्यापक बना दिया गया।

पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी गोतस्कर घायल होकर गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। थाना जयसिंहपुर क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी गोतस्कर विनोद यादव पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को इलाज के लिए 100 बेड अस्पताल बीरसिंहपुर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, 19ध्20 मई की रात करीब 1रू15 बजे जयसिंहपुर पुलिस अंबेडकरनगर से सेमरी रोड पर हालापुर के पास बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और पुलिस के रोकने के बावजूद बैरियर तोड़ते हुए आगे निकल गया। पुलिस टीम ने ट्रक का पीछा किया। कुछ दूरी पर पहुंचने पर ट्रक में सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद यादव पुत्र राजनारायण यादव निवासी ग्राम ख्वाजापुर, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर बताया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें तीन मुकदमे गोकशी से संबंधित हैं। वह गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित चल रहा था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले थाना जयसिंहपुर क्षेत्र में हुई गोकशी की घटना में भी उसकी संलिप्तता सामने आई थी। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह ट्रक का इस्तेमाल गोकशी की घटनाओं में करता था। उसके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से जा घुसी मिनी बस, ड्राइवर समेत 8 श्रद्धालु घायल

आर्यावर्त संवाददाता

जालौन। डकोर थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह करीब चार बजे फूलपुरा के पास किमी संख्या 170 पर चित्रकूट से दर्शनार्थियों को लेकर राजस्थान जा रही मिनी बस चालक को झपकी आने से आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस चालक समेत आठ श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है। आगे जा रहे वाहन को चालक लेकर भाग निकला।

मिनी बस चित्रकूट में दर्शन कर मंगलवार देर रात चित्रकूट से निकली थी। घायलों ने बताया कि चालक को झपकी आने और आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित हो मिनी बस आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। घायल के अनुसार मिनी बस की रफ्तार उस समय करीब 60 किलो मीटर प्रति घंटा थी। मिनी बस चालक कमल सिंह ने बताया कि बस में बच्चों समेत कुल 18 यात्री सवार थे। हादसे में चालक समेत आठ लोगों को चोटें आई हैं। चालक के हाथ में चोट है।

सभी घायल राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ ज़िले के थाना बास दयाल क्षेत्र कराना के रहने वाले हैं।

पप्पू राम गुप्ता, 55 वर्ष, पुत्र मामलचंद गुप्ता

कुसुम देवी, 50 वर्ष, पत्नी पप्पू राम गुप्ता

नीमा देवी, 35 वर्ष, पत्नी मुकेश चंद्र गुप्ता

रेखा गुप्ता, 36 वर्ष, पत्नी पवन कुमार गुप्ता

किशन लाल सोनी, 55 वर्ष, पुत्र ताराचंद

जयद्रा, 52 वर्ष, पत्नी किशन लाल सोनी

बस चालक कमल सिंह राजपूत

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण के सरकारी दावों पर उठाए सवाल

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार/सुलतानपुर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को महाकाल मंदिर पहुंचे। उनके आगमन पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं, व्यापारियों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और जयघोष के बीच श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रदेश में गायों की स्थिति को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कागजों और आंकड़ों में गायों की स्थिति अत्यंत बेहतर दिखाई जाती है, जबकि जमीनी स्थिति अलग नजर आती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं और सरकार द्वारा गायों के संरक्षण के लिए बड़े बजट तथा गांव-गांव गौ आश्रय स्थल बनाने की बातें कही जाती हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति का आकलन जनता स्वयं कर सकती है। उन्होंने पशुपालन विभाग के बजट और गौशालाओं से जुड़े सरकारी दावों का उल्लेख करते हुए कहा कि कागजों में गायों को अत्यधिक सुविधाएं मिलती दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविक हालात अलग हैं। उन्होंने अधिकारियों, पत्रकारों और आम लोगों के बयानों का भी जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने कुड़वार बाजार क्षेत्र में एक गौशाला निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से गौशाला निर्माण के लिए 'एक नोट' यानी एक रुपये के सहयोग की अपील की। मौके पर कुछ लोगों से सहयोग राशि भी एकत्र की गई। इस दौरान दयाराम अग्रहरि ने घोषणा की कि कुड़वार बाजार में जल्द ही एक गौशाला का निर्माण कराया जाएगा।

बलिया से खरीदी गई थी कत्ल में इस्तेमाल हुई कार, सीबीआइ ने तीन ठिकानों पर दी दबिश

आर्यावर्त संवाददाता

बलिया। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) रहे चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में इस्तेमाल की गई सिल्वर रंग की निशान माइक्रा कार का सुराग बलिया जिले में मिला है।

सीबीआइ और बंगाल पुलिस की टीम ने मंगलवार देर रात बांसडीह रोड क्षेत्र में तीन स्थानों पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि हत्या में प्रयुक्त कार बांसडीह रोड क्षेत्र के फुलवरिया निवासी जितेंद्र सिंह की थी।

पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि उसने यह कार घटना से पांच दिन पहले, एक मई को शीतल दवनी गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु को बेची थी। छह मई को पश्चिम बंगाल में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

जितेंद्र सिंह के अनुसार, उसने वर्ष 2025 में छठ पर्व के दौरान फुलवरिया निवासी दीपक से यह कार 35 हजार रुपये में खरीदी थी। 30 अप्रैल को दीपक और मनु ने उससे संपर्क कर कार खरीदने की बात कही। दोनों ने उसे बताया कि कार बेचने पर उसे 15 हजार रुपये का लाभ होगा। इसके बाद जितेंद्र ने एक मई को 35 हजार रुपये में खरीदी गई कार 50 हजार रुपये में मनु को बेच दी।

अर्पित बॉक्सिंग चौंपियनशिप खेलने जुलाई में जाएंगे बैंकॉक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। एमजीएस का बॉक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने जाएगा थाईलैंड।

बताते चले एमजीएस इंटर कॉलेज के कक्षा 10 का छात्र बॉक्सर अर्पित निषाद एशियन आर्म बाक्सिंग चौंपियनशिप 2026 में प्रतिभाग करने जुलाई में बैंकाक (थाईलैंड) जाएंगे। अर्पित ने यह उपलब्धि पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम, सुलतानपुर में हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत कर हसिल किया था। अर्पित अपने विद्यालय में खेल अध्यापक राजेश कन्नौजिया और कोच शुभम धुरिया की देखरेख में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिसके उपलक्ष्य में आज अर्पित निषाद को विद्यालय प्रधानाचार्य महेश कुमार सिंह और उप प्रधानाचार्य विचित्र वीर सिंह ने सम्मानित किया।

विद्यालय के अध्यक्ष संजय सिंह, प्रबंधक डॉ विनोद कुमार सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि अर्पित की यह उपलब्धि सिर्फ जनपद के लिए ही गौरव की बात नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव और हर्ष की बात है। अर्पित के स्वागत के समय राजेश कुमार कनौजिया, दिलीप सिंह, राकेश सिंह, दीपक सिंह, श्याम लाल निषाद, वैभव सिंह, अजय, धर्मेंद्र पांडे, राम प्रकाश, अशोक कुमार सिंह, रत्नाकर, सुनील कुमार सिंह, मो अशहद, शमीम, पवन सिंह, अम्बरीष, सुमित, अंजनी, किरन, मधुलिका, प्रज्ञा, अंजली आदि अध्यापक उपस्थित रहे।

राहुल गांधी के दौरे से पहले गरमाई सियासत, अमेठी में पोस्टर वार और गौरीगंज में भाजपा का प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

अमेठी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक दिवसीय अमेठी दौरे से पहले जिले का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा को निशाने पर लिया गया है।

चस्पा पोस्टर में सवाल उठाया गया है कि "2 साल किशोरी लाल तुमने क्या किया?" साथ ही आरोप लगाया गया है कि सांसद बनने के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर केवल एक स्कूल बस दी गई, वह भी कांग्रेस नेता के स्कूल में, जबकि एक एम्बुलेंस उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल को उपलब्ध कराई गई।

इसके अलावा लगाए गए अन्य पोस्टरों में सांसद किशोरी लाल शर्मा के दो वर्षों के कार्यकाल की तुलना पूर्व सांसद स्मृति जुबिन इरानी के

पांच वर्षों के कार्यकाल से की गई है। पोस्टरों में दावा किया गया है कि स्मृति ईरानी के कार्यकाल में अमेठी में कई विकास कार्य कराए गए थे, जिनका भी उल्लेख किया गया है।

ये पोस्टर कांग्रेस कार्यालय, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज और कलेक्ट्रेट परिसर समेत कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। पोस्टर वार के बाद जिले में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

भाजपा ने राहुल के अमेठी दौरे से पहले किया प्रदर्शन

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेठी दौरे से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ प्रदर्शन कयि। बुधवार सुबह गौरीगंज के फल मंडी तिराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'राहुल गांधी वापस जाओ', 'राहुल गांधी जवाब दो, अपने पीए का हिसाब दो' और 'किशोरी लाल जवाब दो' जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस पर अमेठी की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब अपने सांसद और कांग्रेस नेतृत्व से विकास कार्यों का हिसाब मांग रही है। राहुल गांधी के आगमन से पहले हुए इस विरोध प्रदर्शन ने जिले की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री विषूव मिश्रा, महेश सोनी, जिला उपाध्यक्ष आशा वाजपेयी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। लखनऊ खंडपीठ ने ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, सुलतानपुर के प्राचार्य को एक स्टाफ नर्स द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति की एकल पीठ द्वारा पारित किया गया।

मामला रिट-ए संख्या 3705/2026 से संबंधित है, जिसे कीर्ति श्रीवास्तव ने अधिवक्ता अजय बहादुर के माध्यम से दाखिल किया था। याचिका में मांग की गई थी कि याचिकाकर्ता को स्टाफ नर्स के पद पर कार्य करने दिया जाए तथा उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा या उत्पीड़न न किया जाए। इसके अतिरिक्त, 19 फरवरी 2026 को प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत उनके प्रत्यावेदन के निस्तारण की भी मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया, जिसके कारण उनके प्रत्यावेदन पर शीघ्र निर्णय आवश्यक है। बाद में याचिकाकर्ता की ओर से राहत की मांग को केवल प्रत्यावेदन के निस्तारण तक सीमित कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने भी प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निस्तारण कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि प्राचार्य ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, सुलतानपुर, याचिकाकर्ता के 19 फरवरी 2026 के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश पारित करें।

संतकबीर नगर में पेट्रोल-डीजल का हाहाकार, 32 पंप सूखे, जनजीवन अस्त-व्यस्त

आर्यावर्त संवाददाता

संतकबीर नगर। जिले में पेट्रोल-डीजल का संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालात यह हैं कि जिले के 72 पेट्रोल पंपों में से 32 पूरी तरह ड्राई हो चुके हैं, जबकि शेष पंपों पर भी कभी सुबह तो कभी शाम को तेल खत्म होने की सूचना चस्पा की जा रही है। जरूरत के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई न मिलने से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

जहां तेल मिलने की सूचना मिल रही है, वहां दोपहिया और चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग जा रही हैं। कई लोग घंटों इंतजार के बाद भी बिना तेल लिए वापस लौटने को मजबूर हैं। तीन दिन पहले मेंहदावल क्षेत्र के दो पेट्रोल पंपों पर तेल वितरण के दौरान मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। अधिक भीड़ के कारण कई जगहों पर शांति व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। वाहन चालकों के साथ पेट्रोल पंप संचालक भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने-जाने में गंभीर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी।

जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने कितने पेट्रोल पंप ड्राई है, इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। कहा कि उपभोक्ताओं को दिक्कत न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों से जरूरत से ज्यादा तेल न लेने की अपील भी की जा रही है।

विकास कार्य भी प्रभावित

पेट्रोल-डीजल संकट का असर सरकारी और निजी विकास कार्यों पर भी दिखाई देने लगा है। सड़क निर्माण, मिट्टी भराई और मशीनों से होने वाले अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंप संचालकों का कहना है कि डिपो से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है, जिससे पंप ड्राई हो रहे हैं। प्रशासन से जल्द सप्लाई सामान्य कराने की मांग की जा रही है। मेंहदावल एसडीएम अरुण कुमार ने बताया कि नियमित रूप से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई आ रही है। मांग अधिक होने के कारण अस्थायी समस्या उत्पन्न हो रही है।

मेंहदावल में सबसे ज्यादा असर, पंपों पर उमड़ी भीड़

नगर पंचायत मेंहदावल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल-डीजल का संकट और गहरा गया है। कई पेट्रोल पंपों के ड्राई होने से किसान, व्यापारी और आम लोग परेशान हैं। बौरव्यास स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार को तेल पहुंचने की खबर फैलते ही बाइक, कार और ट्रैक्टरों की लंबी कतार लग गई। सुबह से ही लोग तेल लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करना पंप संचालकों के लिए मुश्किल हो गया। कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं धर्मसिंहवा क्षेत्र के महादेवा नानकार पेट्रोल पंप पर भी पूरे दिन भारी भीड़ लगी रही। ईंधन संकट का सबसे ज्यादा असर किसानों और व्यापारियों पर पड़ रहा है। डीजल न मिलने से ट्रैक्टर और पंपिंग सेट बंद पड़े हैं, जबकि व्यापारी माल ढुलाई नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल वाहन और एंबुलेंस तक के लिए ईंधन जुटाना चुनौती बन गया है।

दवा व्यापारियों का प्रदर्शन, ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर उठाए सवाल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। बुधवार को दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही दवाओं की अनियंत्रित बिक्री और नकली दवाओं के बढ़ते खतरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी विभिन्न मांगों को सामने रखा।

दवा व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका विरोध जनता या मरीजों के खिलाफ नहीं है। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी मेडिकल स्टोर खुले रखे गए हैं और दुकानदार काम करते हुए ही अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त निगरानी के दवाएं बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी और दवाओं की गुणवत्ता का सही सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ सकता है। संघ ने मांग की कि ऑनलाइन दवा बेचने वाले हर प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनिवार्य तैनाती हो और उसका कड़ाई से सत्यापन कराया जाए। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से बिक रही नशीली और प्रतिबंधित दवाओं पर तुरंत रोक लगाने की भी अपील की गई। व्यापारियों ने डार्क वेबसाइट्स और फर्जी ऑनलाइन पोर्टलों के जरिए बाजार में पहुंच रही नकली दवाओं पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि भारी छूट का लालच देकर कई अवैध प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं, जो बिना किसी पंजीकरण के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को समय-समय पर दवाओं की सैंपलिंग और जांच करानी चाहिए।

भविष्य की रणनीति पर व्यापारियों ने कहा कि फिलहाल वे जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहते, इसलिए दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश को एआई हब बनाने की तैयारी, ‘एआई सिटी’ के रूप में विकसित होगा लखनऊ, मुख्यमंत्री ने की डाटा सेंटर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं प्रसंस्करण की समीक्षा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश की भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विषयों—उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर (यूपीडीसीसी), “प्रोजेक्ट गंगा” तथा गेहूं के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क एवं विकास उपकर में संभावित छूट—की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश को भविष्य की प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अभी से तैयार करना होगा।यूपीडीसीसी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि डाटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित न रहकर प्रदेश के अन्य हिस्सों तक विस्तारित किया जाए। उन्होंने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र से इसकी शुरुआत की संभावना पर बल देते हुए कहा कि वहां बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध है। साथ ही, टाटा समूह सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों से संवाद स्थापित कर लखनऊ को “एआई सिटी” के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर प्रदेश को भारत और ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई कंप्यूट पावर सेंटर बनाने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और उच्च तकनीकी विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रस्तुतीकरण में इसे केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि अगले 50 वर्षों की आर्थिक संरचना का आधार बताया गया। इसके तहत वर्ष 2040 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था, 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और 5 गीगावॉट एआई कंप्यूट कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2040 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड सेवाएं, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर आधारित होगा। इन क्षेत्रों का संयुक्त वैश्विक बाजार 29 से 48 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत के लिए एआई सॉफ्टवेयर, क्लाउड सेवाएं, साइबर सुरक्षा, एयरोस्पेस और ईवी क्षेत्र भविष्य के आर्थिक इंजन के रूप में उभरेंगे।उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, विशाल भूमि उपलब्धता, बड़ी युवा आबादी, तेजी से विकसित हो रहे आधारभूत ढांचे और मजबूत नेतृत्व को राज्य की प्रमुख ताकत बताया गया। बैठक में कहा गया कि राज्य का इनलैंड लोकेशन समुद्री जोखिमों और चक्रवातों से सुरक्षित है, जबकि एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक नेटवर्क और विद्युत ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। आईआईटी कानपुर, एनआईटी प्रयागराज और 50 से अधिक इंजीनियरिंग संस्थानों के कारण प्रदेश में पर्याप्त तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध है।बैठक में उत्तर प्रदेश को “एशिया का सबसे सुरक्षित, विस्तार योग्य और परस्पर जुड़ा इनलैंड एआई क्षेत्र” बताया गया। कहा गया कि देश के अधिकांश प्रमुख फाइबर नेटवर्क उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं और राज्य सभी समुद्री केबल लैंडिंग पॉइंट्स से जुड़ा हुआ है। राज्य के भीतर कम विलंबता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध होने से वैश्विक तकनीकी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश कम लागत और बेहतर विस्तार क्षमता वाला एआई इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र बन सकता है।मुख्यमंत्री ने “प्रोजेक्ट गंगा” यानी गवर्नेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि चयनित युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य करने वाली कंपनियों को भी इन प्रशिक्षित युवाओं की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया।बैठक में बताया गया कि प्रोजेक्ट गंगा ग्रामीण उत्तर प्रदेश में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने की महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य केवल इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि टेलीमेडिसिन, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, ई-गवर्नेंस, डिजिटल रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत 10 हजार से अधिक युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 50 हजार प्रत्यक्ष और एक लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक घरों को फाइबर आधारित हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रत्येक डिजिटल सेवा प्रदाता अपने क्षेत्र में 200 से 300 घरों को जोड़ सकेगा। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लगभग 50 प्रतिशत महिला उद्यमियों को शामिल करने की योजना बनाई गई है।बैठक में कहा गया कि केवल मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से सीमित सेवाएं संभव हैं, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि, ड्रोन निगरानी, स्मार्ट गांव, वर्चुअल लैब, टेलीमेडिसिन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सेवाओं के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड आवश्यक है। परियोजना के तहत प्रत्येक डिजिटल सेवा प्रदाता को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल इसे 21 प्राथमिक जिलों में प्रायोगिक रूप से लागू करने की तैयारी चल रही है।मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा करते हुए मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताई। उन्होंने मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, पर्वों के दौरान प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

मुख्यमंत्री ने अल नीनो के संभावित प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में फसलों पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए प्रदेश को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने मजबूत खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 372 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है, जबकि कुल उपलब्धता 407 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचती है। लगभग 2.88 करोड़ किसान गेहूं उत्पादन से जुड़े हैं, लेकिन सीमित प्रसंस्करण क्षमता के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं कच्चे रूप में दूसरे राज्यों में चला जाता है, जिससे मूल्य संवर्धन, कर राजस्व और रोजगार के अवसर प्रदेश से बाहर चले जाते हैं।प्रदेश में वर्तमान में 559 रोलर फ्लोर मिल्स हैं, जिनकी कुल मिलिंग क्षमता 218.4 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन वास्तविक उपयोग 126.45 लाख मीट्रिक टन तक सीमित है। इसके अतिरिक्त 40 हजार से अधिक आटा चक्कियां संचालित हैं। समिति ने सुझाव दिया कि राज्य में पंजीकृत मिलों द्वारा प्रदेश के भीतर प्रसंस्करण के लिए खरीदे गए गेहूं पर मंडी शुल्क और विकास उपकर में छूट दी जाए, जबकि व्यापारिक गतिविधियों पर यह सुविधा लागू न हो।

यूपी बनेगा ग्लोबल एआई हब... डाटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा में बोले सीएम योगी– लखनऊ को करें 'एआई सिटी' के रूप में विकसित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े तीन अहम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि डाटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। इसकी शुरुआत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र से की जा सकती है जहां बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने टाटा समूह समेत बड़ी टेक कंपनियों से संवाद कर लखनऊ को 'एआई सिटी' के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।'

प्रोजेक्ट गंगा' यानी गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुने गए डिजिटल उद्यमियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण करने वाली कंपनियां भी इन युवाओं का उपयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने डिजिटल उद्यमियों को शुरुआत से ही इंसेंटिव देने को कहा।

प्रोजेक्ट गंगा के तहत 10 हजार से अधिक युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा, जिससे 50 हजार प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। 20 लाख से अधिक घरों को फाइबर आधारित हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। योजना में 50% महिला उद्यमियों को जोड़ने का लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल 21 जिलों में पायलट के तौर पर शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाए। मंडियों में साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, त्योहारों पर लाइटिंग, अतिक्रमण हटाने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न सुरक्षा के लिए प्रदेश को अभी से तैयार रहना होगा। यूपी देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। 2025-26 में 372 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। प्रदेश में 559 रोलर फ्लोर मिल्स हैं जिनकी क्षमता 218.4 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन उपयोग सिर्फ 126.45 लाख मीट्रिक टन हो रहा है।

छह साल बाद सूचना विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को राहत, बढ़े पारिश्रमिक को मंजूरी

लखनऊ। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निदेशक सूचना विशाल सिंह ने विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को संशोधित और बढ़े हुए पारिश्रमिक के भुगतान को मंजूरी दे दी है। करीब छह वर्षों से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जिसके चलते कर्मचारी लंबे समय से पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग कर रहे थे।विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा इस विषय पर विस्तृत परीक्षण कर शासनादेशों के अनुरूप संस्तुति तैयार की गई थी। शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक और आउटसोर्स सेवा निगम की व्यवस्था के तहत विभाग में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मियों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण किया गया है।स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार विभाग में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मियों को अब निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का लाभ मिलेगा।

बस्ती मंडल आरएमओ कार्यालय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर न मिलने पर मंत्री मनोज पांडेय नाराज

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने बस्ती मंडल के आरएमओ कार्यालय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगी होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने तत्काल दोनों तस्वीरें कार्यालय में लगाने के निर्देश दिए। यह मामला बुधवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया।कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय की अध्यक्षता में खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें गेहूं क्रय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन वितरण व्यवस्था और आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में राज्यमंत्री सतीश चंद्र मिश्रा, प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित जनपदों के अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी गेहूं क्रय केंद्रों का संचालन गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, क्योंकि किसान देश के अन्नदाता हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक क्रय केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, बोरे, उपकरण और भंडारण की सुविधा 48 घंटे के भीतर शत-प्रतिशत उपलब्ध कराई जाए। इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीब और जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है।

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त चेयरमैन सोहिल अख्तर अंसारी की अध्यक्षता में बुधवार को विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा प्रदेश और देश से जुड़े जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को अधिक सक्रिय बनाते हुए जनसरोकारों से जोड़ने का संकल्प लिया।बैठक में प्रदेश प्रभारी रूबी खान तथा प्रदेश सह प्रभारी महमूद खान की उपस्थिति रही। बैठक का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष (संगठन प्रभारी) शाहनवाज खान ने किया।बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश चेयरमैन सोहिल अख्तर अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सर्वधर्म समभाव, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि गांव-गांव और वार्ड स्तर तक पहुंचकर आम जनता की समस्याओं को उठाया जाए तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जाए।प्रदेश प्रभारी रूबी खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के अधिकार, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाती रहेगी।

नि:शुल्क दोना मेकिंग मशीन वितरण योजना शुरू, 10 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित निःशुल्क टूल किट्स वितरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सेमी मोटराइज्ड दोना मेकिंग मशीन के चयन और वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों तथा दोना-पत्तल निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को निःशुल्क मशीन उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 10 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

नव नियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को डिप्टी सीएम केशव मौर्य की नसीहत, गांवों के विकास को दें प्राथमिकता

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नव नियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें ग्रामीण जनता की सेवा पूरे समर्पण भाव से करने और गांवों के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी प्रतिभा, क्षमता और प्रशासनिक दक्षता का भरपूर उपयोग करते हुए सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दायित्व निभाएं।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी ग्रामीण विकास व्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि गांवों में संचालित सरकारी योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन इन्हीं के माध्यम से होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण सड़क, स्वच्छता, पेयजल तथा आजीविका से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।उन्होंने अधिकारियों को केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि जनसेवक की भावना से कार्य करने की सीख देते हुए कहा कि ग्रामीण जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और देश का विकास संभव है।उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नव नियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों का नियमानुसार प्रशिक्षण शीघ्र कराया जाए तथा उन्हें फील्ड में तैनाती भी समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए।गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के माध्यम से चयनित खण्ड विकास अधिकारियों में से 42 अधिकारियों ने मंगलवार को जवाहर भवन स्थित आयुक्त कार्यालय, ग्राम्य विकास विभाग में आयुक्त ग्राम्य विकास जी.एस. प्रियदर्शी के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की।इस अवसर पर आयुक्त ग्राम्य विकास जी.एस. प्रियदर्शी ने नव नियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे निष्ठा, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

• संक्षेप •

महिगवां में पेट्रोल पम्प पर देर रात लूट, चौकीदार से मारपीट ; बदमाश नकदी और मोबाइल लेकर फरार

लखनऊ। महिगवां थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पम्प पर देर रात लूट की घटना सामने आई है। बैटरी रिक्शा से पहुंचे अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पम्प से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। विरोध करने पर पम्प पर मौजूद चौकीदार के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है।पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 मई 2026 की रात करीब एक बजे की है। थाना महिगवां क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर निवासी ऋषि यादव ने थाना महिगवां में तहरीर देकर बताया कि उनके पेट्रोल पम्प पर बैटरी रिक्शा से आए अज्ञात व्यक्तियों ने लगभग 8100 रुपये नकद और मोटोरोला कंपनी का एक मोबाइल फोन छीन लिया। घटना के दौरान बदमाशों ने पम्प पर मौजूद चौकीदार विपिन कुमार के साथ मारपीट भी की और मौके से फरार हो गए।तहरीर के आधार पर थाना महिगवां में मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(1) और 115(2) में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।घटना के खुलासे और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए थाना महिगवां पुलिस द्वारा दो विशेष टीमों का गठन किया गया है।

नाली विवाद में युवक चढ़ा मोबाइल टावर पर, दुबग्गा पुलिस की सूझबूझ से सकुशल उतारा गया ; दोनों पक्षों में फिर हुआ समझौता

लखनऊ। दुबग्गा थाना क्षेत्र में नाली के पानी की निकासी को लेकर पड़ोसियों के बीच चल रहे विवाद ने बुधवार सुबह अचानक तनावपूर्ण मोड़ ले लिया, जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दुबग्गा पुलिस ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को समझा-बुझाकर सकुशल नीचे उतार लिया। बाद में दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराकर पुनः समझौता भी करा दिया गया।पुलिस के अनुसार, 20 मई 2026 को सुबह करीब 7:30 बजे यूपी-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुर्दापुर निवासी अलीम पुत्र अनीश अहमद, पड़ोस में रहने वाली साजिया पत्नी मोहम्मद मेराज से मकान के सामने नाली के पानी के निकास को लेकर हुए विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। सूचना मिलते ही थाना दुबग्गा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और काफी देर तक समझाइश तथा बातचीत के बाद युवक को सुरक्षित रूप से मोबाइल टावर से नीचे उतार लिया गया। घटना के दौरान पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए किसी भी अप्रिय स्थिति को उत्पन्न नहीं होने दिया।पूछताछ में अलीम ने पुलिस को बताया कि नाली विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले ही समझौता हो चुका था, लेकिन उसे आशंका थी कि मामले में दोबारा आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की जा सकती है।

भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान, 30,160 मेगावाट पीक डिमांड पूरी

लखनऊ। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 30,160 मेगावाट की पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया है। प्रदेश में बिजली की मांग और खपत लगातार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच रही है तथा पिछले तीन वर्षों की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल रहा, जहां रिकॉर्ड स्तर की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।ऊर्जा विभाग के अनुसार बीते दिवस शाम प्रदेश की पीक डिमांड 30,160 मेगावाट दर्ज की गई, जिसे बिना किसी बड़े व्यवधान के पूरा किया गया। इसे प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक बिजली आपूर्ति में शामिल माना जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान बढ़ती मांग के बावजूद निर्बाध बिजली आपूर्ति को ऊर्जा विभाग की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग मजबूत विद्युत प्रबंधन और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना, ट्रांसमिशन एवं वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा निरंतर निगरानी के चलते प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में नई

बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के सहारे लखनऊ में चला रहा था क्लीनिक, बीकेटी पुलिस ने किया गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कमिश्नरेट की बीकेटी पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था और क्षेत्र में क्लीनिकनुमा दुकान संचालित कर लोगों का उपचार भी कर रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपित ने कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भारतीय पासपोर्ट तक हासिल कर लिया था।पुलिस के अनुसार, मामले का खुलासा 16 मई 2026 को उस समय हुआ जब थाना बीकेटी में तैनात उपनिरीक्षक योगेन्द्र कुमार ने सूचना दी कि एक व्यक्ति, जिसकी पहचान अरूप बख्शी पुत्र खोकेन बख्शी के रूप में हुई, मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है और भारत में अवैध रूप से निवास कर रहा है। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर खुद को भारतीय नागरिक दर्शाया और सरकारी पहचान पत्र बनवा लिए।सूचना के आधार पर थाना बीकेटी में मुकदमा अपराध संख्या 183/2026 के तहत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता तथा विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14(ग) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपित बीकेटी क्षेत्र में एक छोटी क्लीनिक अथवा दुकान संचालित कर लोगों को दवा और उपचार उपलब्ध करा रहा था। वह स्वयं को भारतीय नागरिक बताकर क्षेत्र में रह रहा था और कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेज प्राप्त कर चुका था।पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना और साक्ष्यों के आधार पर 20 मई 2026 को तड़के करीब 2:10 बजे किसान पथ स्थित विपश्यना ध्यान केंद्र फ्लाईओवर के नीचे से आरोपित को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपित ने भारत में अवैध रूप से रहने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पहचान पत्र बनवाने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक, उसने बीकेटी क्षेत्र में क्लीनिकनुमा दुकान चलाकर लोगों को दवा देने की बात भी स्वीकार की है।गिरफ्तार आरोपित की पहचान अरूप बख्शी पुत्र खोकेन बख्शी, उम्र करीब 37 वर्ष, मूल निवासी देवभोग जिला नरैल, बांग्लादेश के रूप में हुई है। वर्तमान में वह मूसानगर अस्ति रोड, थाना बक्शी का तालाब क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, वह खुद को चिकित्सक बताता था।गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपित के पास से एक आधार कार्ड, 300 रुपये नकद और ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।इस कार्रवाई को थाना बीकेटी पुलिस टीम ने अंजाम दिया, जिसमें उपनिरीक्षक रामबालक सिंह, उपनिरीक्षक प्रतीक कुमार शर्मा, कांस्टेबल साजिन्द्र पालीवाल, देवराज सिंह, अंशु कुमार तथा चालक कांस्टेबल दिलीप कुमार शामिल रहे।

भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश ने बनाया बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड, 30160 मेगावाट पीक डिमांड पूरी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में बीते दिवस शाम 30,160 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो अब तक की सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति में शामिल है। पिछले तीन वर्षों की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है, जहां रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की मांग को पूरा किया गया।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग द्वारा मजबूत विद्युत प्रबंधन और आधारभूत संरचना के विस्तार के जरिए प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग का दावा है कि नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना, ट्रांसमिशन एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण और लगातार निगरानी के कारण प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।ऊर्जा विभाग के अनुसार, देशभर में भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। बीते दिवस पूरे देश में बिजली की पीक डिमांड 260 गीगावाट दर्ज की गई। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में उत्तर प्रदेश द्वारा 30,160 मेगावाट की मांग को सफलतापूर्वक पूरा करना ऊर्जा प्रबंधन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत कर्मियों और अधिकारियों से अपील की है कि गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरी सतर्कता और समर्पण के साथ कार्य करते हुए विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और सभी के सहयोग से प्रदेश में मजबूत बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

मियावकी वन तकनीक से हरित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम

वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मियावाकी तकनीक एक बेहद प्रभावी और लोकप्रिय विधि बन गई है। जापानी वनस्पतिशास्त्री डॉ. अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित यह तकनीक केवल 2-3 वर्षों में बंजर भूमि को घने, आत्मनिर्भर सूक्ष्म वनों में बदल देती है। पारंपरिक वृक्षारोपण की तुलना में यह विधि 10 गुना तेजी से बढ़ती है और 30 गुना अधिक घने जंगल बनाती है, जो शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श है। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मियावकी वन तकनीक तेजी से अपनाई जा रही है। राज्य में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस तकनीक के जरिए शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और खनन प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर हरियाली विकसित की जा रही है। मियावकी पद्धति में स्थानीय प्रजातियों के पौधों को अधिक घनत्व में लगाया जाता है, जिससे मात्र 3 से 5 वर्षों में घना जंगल तैयार हो जाता है।

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 से मियावकी पद्धति के तहत लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2022 में कोटा मण्डल में एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 23 हजार पौधे तथा 0.3 हेक्टेयर में 7 हजार पौधे लगाए गए। वर्ष 2023 में कोटा के भिल्मी क्षेत्र में 6.4 हेक्टेयर भूमि पर 64 हजार पौधों का रोपण किया गया। वहीं गेवरा क्षेत्र में 2 हेक्टेयर भूमि पर 20 हजार पौधे लगाए गए। वर्ष 2024 में कोटा के उच्चभट्ठी क्षेत्र में 3.2 हेक्टेयर में 32 हजार पौधे लगाए गए। इसके अलावा रायगढ़ मण्डल के तिलईपाली और छाल क्षेत्रों में कुल 3.75 हेक्टेयर भूमि पर 37 हजार 500 पौधों का सफल रोपण किया गया।

वर्तमान में राज्य के कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य तेजी से जारी है। बारनवापारा मण्डल में 'हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 6 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं। कोरबा और रायगढ़ क्षेत्रों में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सहयोग से 4 हेक्टेयर क्षेत्र में 40 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है। वहीं विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत महानदीकोलफील्ड लिमिटेड द्वारा 1.9 हेक्टेयर भूमि पर 64 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अरपा नदी के किनारे भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर हरित क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार मियावकी वन सामान्य जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। यह तकनीक वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने, भू-जल स्तर सुधारने और मिट्टी संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन वनों की शुरुआती वर्षों में देखभाल की जाती है, जिसके बाद ये जंगल स्वतः विकसित होने लगते हैं। इससे रखरखाव की लागत कम होती है और लंबे समय तक पर्यावरणीय लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए कोरबा जिले के गेवरा क्षेत्र के 12.45 हेक्टेयर डंप क्षेत्र में 33 हजार 935 मिश्रित प्रजातियों के पौधों का सफल रोपण किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

कोयला खनन के बाद डंप क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी नीचे दब जाती है और ऊपर पत्थर, कोयला अवशेष तथा अनुपजाऊ मिट्टी रह जाती है। ऐसे क्षेत्रों में पौधों का उगना बेहद कठिन माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति और सतत प्रयासों से इस बंजर भूमि को अब हरियाली में बदला जा रहा है। डंप क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट, नीमखली और डीएपी का उपयोग किया गया। जीपीएस सर्वे और सीमांकन के बाद व्यवस्थित गड्ढे तैयार किए गए तथा 3 से 4 फीट ऊंचाई वाले स्वस्थ पौधों का रोपण किया गया। इस क्षेत्र में नीम, शीशम, सिरस, कचनार, करंज, आंवला, बांस, महोगनी, महुआ और बेल जैसी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इससे आने वाले समय में यह क्षेत्र पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के लिए भी उपयुक्त आवास बन सकेगा।

शुरुआती 2-3 वर्षों की देखभाल के बाद, यह वन पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है और इसे किसी उर्वरक या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। रोपण के बाद पौधों की नियमित सिंचाई, खाद, निंदाई-गुड़ाई, घास कटाई और सुरक्षा का कार्य लगातार किया जा रहा है। मृत पौधों का समय पर प्रतिस्थापन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2025 से 2029 तक पांच वर्षों तक रखरखाव के बाद इस विकसित हरित क्षेत्र को साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गेवरा को सौंपा जाएगा। कम जगह में घने जंगल बनाकर शहरों में प्रदूषण (धूल और ध्वनि) को कम करने में सहायक होते हैं। ये वन पारंपरिक वनों की तुलना में 30 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। गेवरा की यह पहल दर्शाती है कि सही योजना, वैज्ञानिक तकनीक और निरंतर प्रयासों से बंजर और पत्थरीली भूमि को भी घने जंगल में बदला जा सकता है।

ओ पी की विकासपरक राजनीति बनाम सिंदूर पार्क ऑक्सीजोन

विकास अपने-आप में एक विस्तृत व बहुआयामी अवधारणा है। ओ पी चौधरी के लिये विकास का आशय केवल बड़े व मेगा प्रोजेक्ट्स को मूर्तरूप देने तक सीमित नहीं है

मुकेश जैन

किसी शहर का सर्वांगीण विकास एक जटिल और श्रम-साध्य मसला है, विशेषकर किसी पुराने बसाहट वाले शहर का व्यवस्थित विकास बहुत ही पेचीदा होता है। इसके लिये शहरवासियों की जरूरतों की ठीक-ठीक समझ, वहाँ की पारिस्थितिक विशेषताओं, सांस्कृतिक परिवेश, परंपराओं व विरासत के साथ संतुलन स्थापित करना , इसके ठीक समानांतर आधुनिक भविष्य की जरूरतों के साथ भी तालमेल कायम रख पाना और इन सबके बीच ठोस व समयबद्ध कार्ययोजना का निर्माण तथा योजनाओं को धरातल पर उतारने का आवेगपूर्ण संकल्प, सभी का एकजायी होना आवश्यक होता है। यह सुखद संयोग है कि रायगढ़वासियों को इन सभी विशिष्ट योग्यताओं से परिपूर्ण ओ पी चौधरी का कुशल नेतृत्व मिला है और इस अंचल से दिली-लगाव रखने वाले विष्णु देव साय मुख्यमंत्री के रूप में हमारे साथ हैं। कहते हैं कि जब नेतृत्व सबल, नियत साफ और सोच बड़ी हो तो जनता के सपनों को न केवल पंख लग जाते हैं वरन एक-एक करके सपने साकार भी होने लगते हैं। रायगढ़ में विगत ढाई वर्षों से चल रहे विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला इसकी बानगी है। इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शहर के हृदय स्थल में नवनिर्मित बेहतरीन ऑक्सीजोन कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के करकमलों से आमजनता को अर्पित हुआ है। निश्चित रूप से यह अवसर रायगढ़ के नव-विकास के शिल्पी ओ पी चौधरी की पीठ थपथपाने और हमारे लाड़ले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करने का क्षण है। यह रायगढ़ के चेहरे पर एक मीठी व लम्बी मुस्कान बिखरने का क्षण है।

अतीत की उपेक्षा और नया संकल्प- जब हम रायगढ़ के अतीत पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि मध्यप्रदेश के धूर-पूर्वी छोर का अंतिम शहर होने के कारण हमारा रायगढ़ दशकों तक भोपाल में बैठे नीति-निर्धारकों की दृष्टि से लगभग ओझल ही रहा। रायगढ़ को 1901 में नगरपालिका परिषद का दर्जा मिला। तब से लेकर 2001 तक 100 वर्षों के लंबे कालखण्ड में रायगढ़ बेहद मंथर गति से यात्रा करता रहा। मध्यप्रदेश के बड़े शहरों की ओट में दुबक कर रायगढ़ यथास्थिति में रहने का अभिशाप झेलता रहा। हमारे आस-पास के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग भी विकास के मामले में हमसे काफी आगे निकल गये। अटल जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दिये जाने के बाद परिस्थितियां बदली। 2002 में रायगढ़ को निगम का दर्जा हासिल हुआ। 2003 में नये नेतृत्व को काम करने का मौका मिला और रायगढ़ उपेक्षा के दौर से बाहर निकलकर विकास की दहलीज छूने लगा। इस दौर में कतिपय उल्लेखनीय काम जरूर हुये लेकिन 100 वर्षों के बैकलॉग के सामने ये नाकाफी थे। चूंकि लंबे समय की जड़ता थी इसलिये विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये फुटकर प्रयासों से काम नहीं चलने वाला था। उसे एकमुश्त बड़ी छलांग लगाने की जरूरत थी और इस सिद्धि के लिये रायगढ़ किसी ताकतवर एवं सक्षम उद्धारक की बांट जोह रहा था। उनकी वर्षों की यह तलाश ओ पी चौधरी तक आकर पूर्ण हुई है। रायगढ़ के वृहत काया-कल्प हेतु चल रहे सौ से अधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स और उन पर ताबड़-तोड़ एक्शन इस बात के जीवंत प्रमाण हैं। विगत दो-ढाई वर्षों के अनथक क्रियाकलापों से ओ पी ने 'एक ही राजनीति- विकास की राजनीति' के मूलमंत्र को कार्य रूप में सिद्ध करके दिखाया है।

विकास अपने-आप में एक विस्तृत व बहुआयामी अवधारणा है। ओ पी चौधरी के लिये विकास का आशय केवल बड़े व मेगा प्रोजेक्ट्स को मूर्तरूप देने तक सीमित नहीं है वरन आम लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन का उत्थान व जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव उनके लिये विकास का असली पैमाना है। विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला- नालन्दा परिसर, केलो-नहर निर्माण, प्रस्तावित रिंग रोड, मेरीन ड्राइव, स्टेडियम का उन्नयन, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, प्रयास विद्यालय, आधुनिक बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन का आधुनिकीकरण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, सीवरेज, सड़क, पुल-पुलियों के साथ ही पहाड़ मंदिर का ईको-सेंटर की तर्ज पर विकास , उर्दना में नगर -वन की स्थापना और शहर के चारों ओर अलग-अलग ऑक्सीजोन का निर्माण यह दर्शाता है कि ओ पी चौधरी लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण बदलाव को लेकर कितने संजीदा हैं। बहुपयोगी सुविधाओं से लैस ऑक्सीजोन - शहर के बीचों-बीच इतवारी बाजार और कृषि-उपज मंडी का बड़ा भूखंड लगभग अनुपयोगी सा पड़ा था। इस पर कभी मल्टीस्टोरी शापिंग काम्प्लेक्स व मल्टी लेबल आधुनिक पार्किंग की योजना बनी और कभी ऑडिटोरियम निर्माण की योजना बनी लेकिन विभिन्न विभागों में सामंजस्य की कमी और राजनीतिक अड़ंगेबाजी के कारण कोई भी योजना परवान नहीं चढ़ सकी। इस बेशकीमती भूखंड का व्यावसायिक उपयोग करके शासन इसे बड़े आर्थिक रिटर्न व एक नियमित आय का जरिया बना सकती थी लेकिन ओ पी चौधरी ने इसे आम जनता के हितार्थ ऑक्सीजोन के लिये चुना और इसके बहुपयोगी स्वरूप की परिकल्पना की तो उसके पीछे गहरी सोच व गूढ़ निहितार्थ हैं। शहर के आस-पास उद्योगों की स्थापना, शहर के भीतर वृहत कांक्रीटीकरण और बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही आदि कारणों से शहर में कार्बनडाइऑक्साइडका स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है। अलग-अलग स्थानों में ऑक्सीजोन के निर्माण के द्वारा ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना आम तौर पर पर्यावरणीय संतुलन कायम करने का एक समाधानकारक व बेहतर विकल्प होता है। नवनिर्मित ऑक्सीजोन में विशेषज्ञों की सलाह पर अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले पेड़-पौधे लगाये गये हैं, बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले-फिसलपट्टी आदि की व्यवस्था है, योग हेतु अलग मंच, ओपन एयर थिएटर सहित वॉकिंग ट्रैक भी है। इससे लगकर एक गेम-जोन व फ़ूडकोर्ट और व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण भी किया गया है। संक्षेप में, जहां एक ओर यह ऑक्सीजोन काफी हद तक प्रदूषण से राहत देने वाला केंद्र होगा वहीं दूसरी ओर यह सैर-सपाटे, योग, स्वच्छ हरित पट्टिका, वॉकिंग, कला मंचन आदि की सुविधाओं से लैस उपयोगी स्वास्थ्य केंद्र , कम्युनिटी मीटिंग और कलात्मक व सांस्कृतिक मेल-जोल के केंद्र के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री साय की मंशा के अनुरूप हुआ नामकरण - इस ऑक्सिजोन के साथ एक विशिष्ट और उल्लेखनीय विषय इसके नाम का चयन भी है। विदित हो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा काश्मीर घाटी में भारतीय महिलाओं के सामने ही उनका सिंदूर मिटा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी नेतृत्व में भारतीय सेना ने अद्भूत शौर्य का प्रदर्शन करते हुये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को ऐसा मुँह-तोड़ जवाब दिया था कि पूरा विश्व अचंभित हो गया।

टिप्पणी

देश की मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक, प्रतिभा पर गिद्धों का डेरा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नीट परीक्षा (नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट) का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करदी गई है।यह नीट परीक्षा देश भर के 22 लाख परीक्षार्थियों ने 3 मई को देश भर के 1500 से अधिक केंद्रों पर दी थी।इस मामले से यह साबित हो गया है कि देश में प्रतिभा पर गिद्धों का डेरा है।अबकी बार इन गिद्धों रूपी मांगीलाल और दिनेश रीयल सेक्टर के जयपुर के कारोबार से जुड़े ने नासिक एक बेहद प्रतिष्ठित प्रेस से पूरा पेपर 30 लाख में खरीदा और उसे सबसे पहले अपने पुत्र को सीकर में उपलब्ध करवाया। उसके बाद जयपुर से महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना,में विभिन्न ठिकानों पर लाखों रुपए में बेच कर लगभग 10 करोड़ रुपए वसूल किए।

ये पेपर 26,27 अप्रैल को खरीदा गया। चुकी सॉफ्ट कॉपी में था इसलिए एक दिन में ही पूरे भारत में सर्कुलेट हो गया था।

सबसे पहले जयपुर में पुलिस को एक गैस पेपर मिला जो 420 प्रश्न का था उसमें केमिस्ट्री के 120 प्रश्न हू ब हु ओरिजनल पेपर में थे ।एक कोचिंग यह जारी किया था तब पुलिस का माथा ठनका तो मालूम हुआ कि पूरा पेपर ही कई विद्यार्थी पर था ।इस पर केंद्रीय मंत्री शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान ने संज्ञान लिया और जांच कराई तो पाया कि पूरे देश में व्हाट्सएप के जरिए फेल गया ।कई लोगों ने पच्चीस हजार में खरीदा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीबीआई की रिपोर्ट पर परीक्षा रद्द कर दी। सीबीआई अभी जांच कर रही है बताया जाता है कि पूरे देश में 100 से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

यह दूसरा मौका जब एनटीए की नीट परीक्षा पर प्रश्न लग
रहे हैं इससे पूर्व 2024 की परीक्षा पर भी सवाल उठे थे।

दरअसल देश में एक तबका ऐसा है कि उसे अपने बच्चों डॉक्टर बनाना है क्योंकि मेडिकल डॉक्टर की आय का कोई ठिकाना नहीं है देश में कुल निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक लाख सीट है और 22 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।यानि कड़ी प्रतियोगिता है।इस लिए लोग गलत रास्ते अपनाते हैं । दिनेश और मांगीलाल के घर चार बच्चों को ,2024, में प्रवेश मिला है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर हमेशा से ही गिद्धों की नजर रही है।इन गिद्धों में दलाल, राजनेता,नौकरशाह शामिल रहे हैं।इनका जाल राज्यों की यूपीएससी, सीएससी,कुछ हद तक यूपीएससी,सेना भर्ती तक फैला हुआ है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा भी इसमें शामिल है। बताया जाता है कि ये लोग सबसे पहले पेपर सेटर से बात करते हैं फिर पता लगाते हैं कि पेपर किस प्रेस में प्रकाशित हो रहा है।बस यही एक कमजोर कड़ी से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं। और मनमाने तरीके से बेच देते हैं।इसमें प्रतिभा शील छात्र पीछे रह जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इन पेपर को कलेक्टर के हवाले कर देते हैं और कलेक्टर इन्हें कोतवाली में रख देता है मगर रात को ही लिफाफे को खोल कर पेपर को फोटो कॉपी कर या पीडीएफ बनाकर सर्कुलेट करदेते है। नेटवर्क इतना तगड़ा है कि प्रत्येक राज्य, महानगर,बड़े शहरों से जिले मुख्यालय तक पहुंचा ही नहीं देते बल्कि रात में ही ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाता है।

ब्लॉग

चिंतन शिविर: साझा दृष्टिकोण के ज़रिए भारत में खेलों के भविष्य को दिशा देना

पुलेला गोपीचंद

दो चिंतन शिविरों का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त करने के बाद, मैं भरोसे के साथ कह ??सकता हूँ कि यह आज भारतीय खेल जगत की सबसे सामयिक और असरदार पहलों में से एक है। हम अपने राष्ट्र की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, एक ऐसा मोड़ जहाँ इरादा, निवेश और प्रेरणा अभूतपूर्व रूप से एक साथ मिल रहे हैं।

पिछले एक दशक में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत में खेल हाशिये से मुख्यधारा में आ गया है। इसके महत्व के प्रति भी साफ तौर पर राष्ट्रीय जागरूकता देखी जा सकती है, न केवल एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि के रूप में, बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव के साधन के रूप में भी। आज, हम एक विशाल और विविध तंत्र देख रहे हैं, जहां राज्य सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, निगम, संघ और ज़मीनी स्तर के संस्थान सभी मिलकर खेलों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।

चिंतन शिविर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है। खेल अपने आप में कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिनमें विनिर्माण, मनोरंजन, फिटनेस, मीडिया और शिक्षा शामिल हैं। यह शिविर इन सभी क्षेत्रों को एक साथ लाने में मदद करता है, जिससे एक साझा दृष्टिकोण बनता है, जो दीर्घकालिक सफलता के लिए बेहद ज़रुरी है। यह देश के सामूहिक दृष्टिकोण को सामने लाता है और साथ ही विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करता है, जिससे अनुकरण और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है।

चिंतन शिविर महज एक सम्मेलन से कहीं बढ़कर, एक शिक्षण तंत्र है। यह इसमें शामिल होने वाले लोगों को विचारों का आदान-प्रदान करने, चुनौतियों को समझने और मिलकर समाधान विकसित करने का अवसर देता है। यह एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में भी काम करता है, सफलता की तमाम कहानियों को सामने लाता है और इस विचार को और पुख्ता करता है कि भारत में खेल महज़ विशिष्ट पदकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भागीदारी, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण भी शामिल है।

फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन और साइक्लिंग प्रतियोगिताओं जैसी सामुदायिक गतिविधियों ने खेल के प्रति हमारे नज़रिए को नया रूप दिया है। आज के वक्त में जोर ₹सभी के लिए खेल₹ के साथ-साथ, उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता पर है। पदक जीतने की आकांक्षाएं और व्यापक भागीदारी अब अलग-अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि वे एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

श्रीनगर में शिविर का आयोजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस शहर की शांत सुंदरता न केवल खेलों की विचारधारा के लिए एक मनोरम पृष्ठभूमि प्रदान करती है, बल्कि शांत चिंतन का भाव भी देती है, जो सार्थक संवाद के लिए बेहद ज़रुरी है।

इस चिंतन शिविर का एक अहम केंद्र बिंदु श्रीनगर खेल संकल्प को अपनाना था। यह संकल्प महज़ एक आशय का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह एक एकीकृत ढांचा है, जो भारतीय खेल जगत के सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को एक साथ बांधता है। साझा लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके, यह एक ऐसा रोडमैप तैयार करता है, जो विखंडन के बजाय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

श्रीनगर खेल संकल्प की असली ताकत विभिन्न भागीदारों—सरकारों, संघों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक मंच पर लाने की क्षमता में निहित है। यह इस विचारधारा को और पुख्ता करता है कि भारत के खेल जगत का उत्थान अलग-थलग प्रयासों से नहीं हो सकता। इसके बजाय, इसे एक समन्वित, सहयोगात्मक दृष्टिकोण से संचालित किया जाना चाहिए, जहां संसाधनों, ज्ञान और विशेषज्ञता को एक साथ लाया जाए।

भारत को 2036 तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल होने की अपनी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए यह समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने के लिए न केवल प्रतिभा की ज़रुरत होती है, बल्कि एक सुचारू तंत्र की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जमीनी स्तर पर पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, उत्कृष्ट कोचिंग, प्रतिस्पर्धा का अनुभव और निरंतर वित्तीय एवं संस्थागत समर्थन शामिल हैं। संकल्प वही रणनीतिक कड़ी है, जो इन सभी तत्वों को एक सुसंगत प्रणाली में जोड़ सकता है।

इन वार्ताओं से जो बात सबसे अधिक उभरकर सामने आई है, वह है इस व्यवस्था में मौजूद आशावाद। सभी का यह मानना ??है कि भारत का खेल भविष्य उज्ज्वल है और सहयोग से हम एक सशक्त, समावेशी और उच्च प्रदर्शन वाली खेल संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं।

चिंतन शिविर कई मायनों में एक अनूठा प्रयोग है, लेकिन यह पहले से ही सफल साबित हो रहा है। यह संवाद, समन्वय और आपसी समझ के महत्व को दर्शाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए, ऐसे मंच न केवल लाभकारी हैं, बल्कि आवश्यक भी हैं।

अगर हम वैश्विक खेल मंच पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को सही मायने में साकार करना चाहते हैं, तो इन संवादों का जारी रहना और इन्हें सामूहिक कार्रवाई से मदद मिलना भी ज़रुरी है। श्रीनगर खेल संकल्प हमें वह दिशा प्रदान करता है। चिंतन शिविर हमें वह मंच प्रदान करता है। ये दोनों मिलकर भारत को अपनी खेल संबंधी आकांक्षाओं को स्थायी ओलंपिक सफलता में बदलने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं।

(लेखक भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच हैं)

एसपी ने जनसुनवाई में सुनीं समस्याएं

आर्यावर्त संवाददाता

फतेहपुर। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बुधवार को थाना जाफरगंज पहुंचकर जनसुनवाई की और आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई के दौरान क्षेत्र से पहुंचे फरियादियों ने अपनी विभिन्न शिकायतें और समस्याएं पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखीं।

एसपी ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए, ताकि आमजन का पुलिस प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो सके। जनसुनवाई के दौरान थाना स्तर के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जनसुनवाई के बाद एसपी ने थाने का निरीक्षण किया। उन्होने कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, हवालात के साथ-साथ परिसर का भी जायजा लिया। उन्होने थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। थाने पर आने वाले पीड़ितों के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए। महिला उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करें।

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में उतरे केमिस्ट

मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

फतेहपुर। जिले के दवा व्यापारियों ने अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री और फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए बुधवार को प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन के बैनर तले जुटे व्यापारियों ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा नियमों को ताक पर रखकर की जा रही दवा बिक्री से न सिर्फ मरीजों की सेहत खतरे में पड़ रही है, बल्कि लाखों छोटे दवा कारोबारियों का अस्तित्व भी संकट में आ गया है।

राधानगर स्थित संगठन कार्यालय से बड़ी संख्या में दवा व्यापारी एकत्र होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ऑनलाइन दवा कंपनियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिना वैध डॉक्टर परामर्श और सत्यापित ई-प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की होम डिलीवरी खुलेआम की जा रही है, जो सीधे तौर पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और नियम 1945 की भावना के विपरीत है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2018 में जारी अधिसूचना जीएसआर 817(ई) और कोविड महामारी के दौरान आपातकालीन व्यवस्था के तहत लागू जीएसआर 220(ई) का अब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। महामारी समाप्त होने के बाद भी ई-फार्मेसी और क्विक कॉमर्स कंपनियां मनमाने ढंग से दवाओं की बिक्री कर रही हैं। व्यापारियों ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट और प्रिडेटरी प्राइसिंग अपनाकर छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रही हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में छोटे दवा विक्रेताओं के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार से की गई कि अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए, बिना वैध एवं सत्यापित ई-प्रिस्क्रिप्शन के दवा डिलीवरी प्रतिबंधित की जाए, जीएसआर 817(ई) एवं जीएसआर 220(ई) अधिसूचनाओं को निरस्त किया जाए, ऑनलाइन कंपनियों की अत्यधिक छूट और मनमानी मूल्य नीति पर नियंत्रण लगाया जाए। व्यापारियों ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के कठिन दौर में जब लोग घरों से निकलने से डर रहे थे, तब दवा विक्रेताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक जीवनरक्षक दवाएं पहुंचाईं। ऐसे में सरकार को स्थानीय दवा कारोबारियों और आम मरीजों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ठोस निर्णय लेना चाहिए। इस मौके पर संगठन के चेयरमैन किशन मेहरोत्रा, अध्यक्ष सुमित रस्तोगी, महामंत्री राजेश सोनी, व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष शिवचंद्र शुक्ला, राजीव गुप्ता, अनिल साहू, अजीत कुमार, गगन अग्रवाल, राजा गुप्ता, यतीश रायजादा, सैय्यद मोनू, ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव, राहुल, मनीष श्रीवास्तव, वीरेन्द्र गुप्ता, हरीश रायजादा, प्रदीप रायजादा, आरिफ अहमद, करण रस्तोगी, राम प्रताप, रवि सोनी, योगेंद्र, प्रभाकर समेत बड़ी संख्या में दवा विक्रेता मौजूद रहे।

अलीगढ़ में ऑनर किलिंग से सनसनी : बेटी के अफेयर से ऐसा नाराज हुआ पिता, हत्या कर खेत में दफनाई लाश, लेकिन मां ने खोल दी पोल

आर्यावर्त संवाददाता

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थाना खैर क्षेत्र के जरारा गांव में ऑनर किलिंग का एक खौफनाक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जुर्म और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपी पिता ने बेटी के शव को अपने ही खेत में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया।

यह पूरी घटना किसी फिल्मी पटकथा की तरह सामने आई है। पुलिस के अनुसार, जरारा गांव का निवासी पूरन सिंह जाटव अपनी 19 वर्षीय बेटी शिवानी के प्रेम प्रसंग से बेहद नाराज था। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ और गुस्से में आकर पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद सबूतों को पूरी तरह छुपाने के इरादे से उसने शव को गांव में स्थित अपने खेत में ले जाकर एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें दबा दिया।

आरोपी पिता अपने इस खौफनाक राज को छुपाने में कामयाब हो जाता, लेकिन मृतका की मां की सजगता ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। शिवानी के अचानक गायब होने के बाद जब उसकी मां खेत की तरफ गई, तो वहां संदिग्ध रूप से खुदी हुई मिट्टी देखकर उसे गहरा शक हुआ। मां को भांपते देर नहीं लगी कि उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हुई है। उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत स्थानीय खैर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी।

पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में निकाला गया शव

सूचना मिलते ही पुलिस महकमे और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। कानूनी नियमों के तहत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में संदिग्ध स्थान पर खुदाई शुरू करवाई गई। कुछ ही देर की खुदाई के बाद जमीन के नीचे से 19 वर्षीय शिवानी का शव बरामद कर लिया गया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई।

आरोपी पिता हिरासत में, जांच जारी

एसपी ग्रामीण मनीष कुमार मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मुख्य आरोपी पिता पूरन सिंह जाटव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

फतेहपुर। हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले बृजेश पुत्र रामविशाल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए मारपीट व लूट करने वाले आरोपियो पर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। एसपी को दिए शिकायती पत्र में बृजेश ने बताया कि वह तहसील चौराहा के निकट हेयर कटिंग सैलून चलाता है। दस अप्रैल को घर जाते समय उसके साथ आर्यन ठाकुर, करन शर्मा, राज शर्मा निवासी तहसील चौराहा ने उसके साथ गाली गलौच व मारपीट कर सोने की चैन एवं दस हज़ार रुपये लूटने का आरोप लगाया। बताया कि उसने घटना की सूचना कोतवाली में दी जिस पर आरोपियों पर एससी एसटी एक्ट समेत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन आरोपियो की गिरफ्तारी नहीं गयी। जिससे आरोपियो के हौसले बुलंद है आरोपियों द्वारा दुकान पर आकर गाली गलौच कर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने दोषियों पर कार्रवाई किये जाने की मांग किया।

हाईवे पर अज्ञात वाहन में घुसी कार, चालक समेत चार युवकों की मौत, दो युवक घायल

आर्यावर्त संवाददाता

अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। गजरौला में हाईवे पर दिल्ली की तरफ जाते समय अज्ञात वाहन में पीछे से वैगनआर कार घुस गई। हादसे में चालक मोहम्मद सलमान (27) समेत चार युवकों की मौत हुई है। जबकि दो युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

सलमान रामपुर के पंखेवालान गेट बमनपुरी का रहने वाला था। तीन मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। रामपुर के पंखेवालान गेट बमनपुरी निवासी तनवीर ने पुलिस को बताया कि उनके भाई मोहम्मद सलमान टैक्सी में वैगनआर कार चलाते थे।

दूसरे प्रदेश के पांच युवक रामपुर में दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रामपुर में उनकी ट्रेन छूट गई। इस कारण बुधवार सुबह वैगनआर में सवार हो गए। उनको सलमान दिल्ली छोड़ने जा रहे थे। करीब 4 बजे उनकी वैगनआर कार ख्यालीपुर ढाल से लगभग 200 मीटर आगे पहुंची थी।

बताया जा रहा है कि यहां पर आगे चल रहे अज्ञात वाहन में कार घुस जाने से कार चालक मोहम्मद सलमान समेत चार युवकों की मौत हो गई। कार में सवार हसनैन व समेतुल इस्लाम घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर यूपी-112 के पुलिस कर्मी पहुंच गए। उन्होंने घायलों को डिडौली कोतवाली क्षेत्र के चौधरपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चारों के शव सीएचसी में लाए गए। यहां से उनको मोर्चरी पर भिजवा दिया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि हादसे में चार युवकों की मौत का मामला सामने आया है। तीन की पहचान नहीं होने के कारण उनके शव मोर्चरी पर रखवाए गए है। उनकी पहचान होने पर ही पता चल सकेगा कि क्या करते थे और कहां जा रहे थे।

भीषण गर्मी के चलते स्कूल 31 मई तक बंद, लू से बचाव के संबंध में अलर्ट जारी

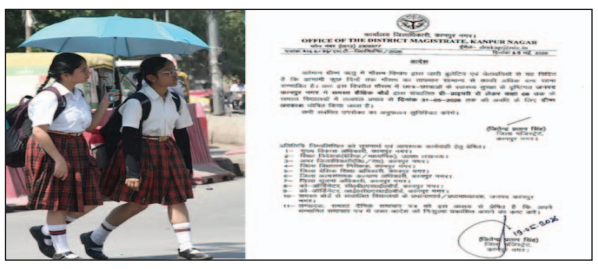

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। लगातार बढ़ रही गर्मी और मौसम विभाग की चेतावनियों के मद्देनजर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक स्कूलों में 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अभी तक ऑरेंज अलर्ट था।

मंगलवार को चकेरी स्थित एयरफोर्स मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सीएसए की मौसम वेधशाला की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 12.30 बजे तापमान 44 डिग्री पर पहुंच गया। यह तापमान दोपहर तीन बजे तक एक ही बिंदु पर बना रहा। तपिश चरम पर रही। लू के थपेड़े अधिक सख्त हो गए। 24 घंटे में चकेरी स्थित एयरफोर्स मौसम केंद्र का तापमान 0.2 और सीएसए की मौसम वेधशाला में 0.8 अधिक दर्ज किया गया।

प्रदेश के एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रभारी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि जब रात और दिन के तापमान में क्रमिक वृद्धि होती है तो शरीर पर हीट स्ट्रेस बढ़ने लगता है। ऐसे में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। सीएसए के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 19 मई के सामान्य औसत से 3.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री अधिक रहा है।

रेड अलर्ट के दौरान यह करें

-दोपहर में 12 बजे से शाम चार तक धूप में बाहर न निकलें

-पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी या ओआरएस का का सेवन करते रहें

-हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें, सिर को ढंक कर रखें

'खेत की सफाई करा देना, जो खर्च होगा दे दूंगा', छात्रा का कत्ल कर अंकुश ने मालिक को किया था फोन, नया खुलासा

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की छात्रा को अगवा कर कल्याणपुर गांव के अंकुश ने उकसिया गांव स्थित ईख के खेत में ले जाकर शादी करने की जिद की। छात्रा ने इन्कार कर दिया। छात्रा का मोबाइल चेक करने पर आरोपी को दूसरे युवक से संबंध का शक हुआ। इससे बौखलाए आरोपी ने छात्रा गला दबाकर हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने खेत मालिक आदेश को साक्ष्य मिटाने के लिए कॉल की थी। आदेश ने आरोपी का मोबाइल भी छिपाया था। जानकारी पुलिस को नहीं देने पर आदेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इसके बाद से उसे जमानत मिल गई। मंगलवार सुबह छात्रा के पिता और परिजन टीपीनगर थाने पहुंचे। उनके पिता ने थाना पुलिस से अब तक की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य आरोपियों नाम प्राथमिकी में शामिल करने की जानकारी मांगी। पुलिस परिजन को बताया कि आरोपी अंकुश को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार शाम उकसिया गांव ले जाया गया था। वहां जाकर क्राइम सीन रिक्रेट करते हुए आरोपी से पूछताछ की गई और उससे वारदात के संबंध में जानकारी ली गई। आरोपी ने बताया कि उसके छात्रा से संबंध थे। फोन पर बातचीत होने के बाद वह उसे बाइक पर बैठाकर उकसिया गांव स्थित ईंख के खेत तक लाया था। इसके बाद आरोपी ने उसे शादी करने की जिद कि लेकिन छात्रा ने साफ कह दिया कि वह अपने माता-पिता की मर्जी से ही शादी करेगी।

आरोपी ने कहा जो खर्च होगा वह दे देगा

छात्रा का मोबाइल चेक करने पर उसे एक लड़के को भेजा गया मैसेज दिखाई दिया। उसे लगा कि इसी वजह से वह शादी से इन्कार कर रही है। आरोपी ने उसके दुपट्टे से ही गला दबाकर हत्या कर दी। यह खेत आरोपी के खेत से पांच सौ मीटर की दूरी पर है। इसके चलते आरोपी खेत मालिक से परिचित है। हत्या के बाद आरोपी ने कॉल कर खेत मालिक आदेश से कहा कि खेत की सफाई करा दे, जो भी खर्च होगा वह दे देगा। आदेश ने संगीन वारदात की जानकारी होने के बावजूद सूचना पुलिस को नहीं दी। आरोपी की कॉल डिटेल से भी उसके आदेश को फोन करने पुष्टि हुई है। पुलिस ने मौका-ए-वारदात से कुछ दूरी से छात्रा का और आरोपी आदेश के घर से अंकुश का टूटा मोबाइल बरामद किया। दोनों मोबाइल आरोपी ने वारदात के बाद तोड़ दिए थे। छात्रा का बैग शव के साथ ही बरामद कर लिया गया था। छात्रा के कपड़े आदि के साथ इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

कंकरखेड़ा-करनावल-किनौनी के उकसिया पहुंचे थे

पुलिस के मुताबिक, छात्रा घर से लगभग 9:45 पर घर से निकली थी। इसके बाद लगभग दस बजे वह रेलवे रोड चौराहे पर पहुंचे। आरोपी से संपर्क होने के बाद यहां कुछ देर खड़ी रही और फिर आरोपी के आने पर उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। इसके बाद आरोपी उसे कंकरखेड़ा, भूनी टोल, करनावल और किनौनी के रास्ते उकसिया के खेत में ले गया था। भूनी टोल व रेलवे रोड चौराहे के पास के फुटेज भी पुलिस को मिले हैं।

धारा बढ़ाने के लिए मांगा जाति प्रमाण पत्र

छात्रा के पिता ने प्राथमिकी में एससी/एसटी एक्ट लगाने की मांग की। इस पर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा ने उनसे कहा कि पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। उन्होंने उनसे जाति प्रमाण पत्र की मांग की और कहा इसके बाद धारा बढ़ाई जाएगी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का कहना है कि इस मामले की जांच जारी है। पीड़ित परिवार को मदद दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

मुरादाबाद में रिटायर्ड डीएसपी ने किया सुसाइड, लाइसेंसी राइफल से मारी गोली, किस वजह से दर्द में थे लखपत सिंह?

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रिटायर्ड डीएसपी ने सुसाइड कर लिया। छजलैट थाना क्षेत्र के रमपुरा गांव में रहने वाले यूपी पुलिस के रिटायर्ड उपाधीक्षक (डीएसपी) 89 वर्षीय लखपत सिंह ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं पुलिस महकमे में भी उनके पुराने साथियों के बीच गहरा दुख देखा जा रहा है।

मंगलवार सुबह जब काफी देर तक लखपत सिंह अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो परिजनों को चिंता हुई। परिवार के लोगों ने पहली मंजिल पर बने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद खिड़की से झांककर देखा गया तो अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। लखपत सिंह का खून से लथपथ शव बेड पर पड़ा हुआ था और पास में उनकी लाइसेंसी राइफल रखी थी। घटना की सूचना मिलते ही छजलैट थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी।

शुरुआती जांच और परिवार के बयान के अनुसार, लखपत सिंह पिछले कुछ समय से गहरे मानसिक तनाव में थे। दरअसल, बीते वर्ष 27 दिसंबर 2025 को उनकी पत्नी का निधन हो गया था। जीवनसंगिनी के निधन के बाद से वे पूरी तरह टूट चुके थे और अकेलेपन का सामना कर रहे थे। परिवार के लोगों का कहना है कि पहले मिलनसार और शांत स्वभाव के रहने वाले लखपत सिंह पिछले कुछ महीनों से काफी गुमसुम रहने लगे थे। उन्होंने लोगों से बातचीत भी कम कर दी थी और ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेले बिताते थे।

बताया जा रहा है कि सोमवार रात भी वे रोज की तरह पहली मंजिल पर बने अपने कमरे में सोने चले गए थे। देर रात उन्होंने अपनी लाइसेंसी राइफल ठुड्डी के नीचे रखकर ट्रिगर दबा दिया। गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सुबह जब वे नीचे नहीं आए तो उनके बड़े बेटे सतवीर ने सीढ़ी लगाकर ऊपर जाकर देखा, जहां पिता का शव पड़ा मिला।

लिस ने घटनास्थल से राइफल जब्त की है

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि गोली बेहद नजदीक से चलाई गई थी, जिससे सिर और चेहरे का हिस्सा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अत्यधिक खून बहने और गंभीर चोट के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से राइफल जब्त कर ली है। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन परिजनों के बयान और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस डिप्रेशन और अकेलेपन को आत्महत्या की मुख्य वजह मान रही है। लखपत सिंह वर्ष 1995 में यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त हुए थे। परिवार में उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

किसान चिंतन शिविर में हरिद्वार पहुंचने की बनाई रूपरेखा

फतेहपुर। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक बैठक में हरिद्वार में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय किसान चिंतन शिविर में पहुंचने की जहां रूपरेखा बनाई गई वहीं बिजली रोस्टिंग का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह गौतम ने की। उन्होने बताया कि आगामी नौ, दस व ग्यारह जून को तीन दिवसीय किसान चिंतन शिविर हरिद्वार पहुंचने की रूपरेखा तय की गई है। रात्रि में बिजली रोस्टिंग का मुद्दा प्रमुखता से रखा गया और नहरों में अंतिम छोर तक पूरा पानी पहुंचाने की चर्चा की गई। संगठन की ब्लाक स्तरीय समीक्षा बैठक की रूपरेखा तय की गई। बैठक में प्रीतम सिंह, छोटे सिंह, डा0 लल्लन, अंकित सिंह चौहान, महेन्द्र सिंह भदौरिया, दीपक गुप्ता, बब्लू सिंह, अजय प्रजापति, उमेश परमार, गुलाब सिंह यादव, सोनू सिंह, अजय सिंह, रघुदेव सिंह, रमन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

ग्रेटर नोएडा में भीषण गर्मी का टॉर्चर! जेवर में 48 डिग्री पहुंचा तापमान... अलर्ट पर प्रशासन और अस्पताल

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में बुधवार को भी भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जेवर क्षेत्र में तापमान 48 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग के अनुसार जिले का अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। लगातार बढ़ती गर्मी और चल रही लू को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जिले में हाई अलर्ट जारी किया है।

सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया, जबकि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। प्रशासन ने लोगों से बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की अपील की है। जिला प्रशासन का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान इसी तरह गर्म बना रह सकता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खाली पेट बाहर न जाएं, हल्के और सूती कपड़े पहनें, सिर को गमछे या टोपी से ढककर रखें, ज्यादा देर तक धूप में काम न करें, बाहर निकलते समय ओआरएस या पानी साथ रखें और साथ ही नारियल पानी का भी सेवन करें। इसके अलावा दही और छाछ का भी सेवन करें। वहीं, भीषण गर्मी को देखते हुए जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है।

30 की रफ्तार से चल सकती हैं गर्म हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। दिन भर आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार पड़ रही लू से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हीट वेव का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ रहा है, जो धूप के संपर्क में काम करते हैं। प्रशासन ने निर्माण स्थलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले संस्थानों को भी निर्देश दिए हैं कि मजदूरों को समय-समय पर पानी और आराम की सुविधा दी जाए। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है, गर्मी और लू से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है।

भीषण गर्मी में भी भारत की इन जगहों पर जमी रहती है बर्फ, मई में प्लान करें ट्रिप

मई के महीने में अब मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। सूरज की लपटों और गर्म हवाओं ने हालत खराब कर दी है। हालांकि इस मौसम में ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बस हरियाली ही देखने को मिलती है। अगर आप इस गर्मी के मौसम में भी स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो जान लें कि आपको कौन सी जगहों पर जाना होगा।

सर्दी हो या फिर गर्मी पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। दरअसल जहां लोग सर्दियों में स्नोफॉल का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं तो वहीं गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग उत्तराखंड, हिमाचल जैसी जगहों पर जाते हैं, लेकिन क्या हो कि आपको अपनी इस ट्रिप में हरियाली के साथ ही बर्फ से ढके पहाड़ों का शानदार व्यू भी देखने को मिले। भारत की ऐसी ही कुछ जगहें हैं जहां पर गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है।मई के महीने में आप यहां की ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

दूर तक बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं...अगर गर्मी में भी ऐसा शानदार नजारा देखने को मिलेगा तो एक रिफ्रेशिंग किक मिलती है, जो आपके स्ट्रेस को दूर कर देंगे। इस भागदौड़ भरी जिंदगी और भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जान लें कि कौन सी जगहों पर आपको बर्फ देखने को मिल सकती है।

लद्दाख का खारदुंग ला

गर्मियों में अगर आपको बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जाना है तो आपको लद्दाख के खारदुंग ला जाना चाहिए। ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है। ये लेह को नुब्रा और श्योक घाटियों सो जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। यहां गर्मियों में भी हर तरफ बर्फ रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि परमिट लेना होगा और हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।

स्पीति घाटी

आप अगर गर्मियों में बर्फ का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी (Spiti Valley) जा सकते हैं। इस जगह को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहां के प्रमुख दर्रों जैसे कुंजुम पास पर गर्मियों में भी बर्फ की चादर बिछी रहती है। इसके अलावा यहां का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है चंद्रताल झील। जहां यहां पर आए हर एक टूरिस्ट का जाने का सपना रहता है।

कश्मीर का गुलमर्ग

बात अगर खूबसूरत वादियों की हो तो कश्मीर को कैसे भूला जा सकता है। गर्मी हो या सर्दी यहां पर आने का हमेशा ही अमेजिंग रहता है। गर्मियों में कश्मीर के गुलमर्ग में आपको बर्फ देखने को मिल सकती है। वैसे तो यहां पर गर्मी के मौसम में बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन यहां की ऊंची चोटियों पर बर्फ जमा रहती है, जैसे अफरवैट पीक पर आप पहले से ही जमा बर्फ एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं। गर्मियों में भी यहां का टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।

रोहतांग पास

सर्दियों में लोग स्नोफॉल के लिए शिमला, कुल्लू और मनाली का रुख करते हैं, लेकिन अगर गर्मियों में आपको बर्फ देखनी है तो मनाली के पास ही आप रोहतांग जा सकते हैं। ये हाई-एल्टीट्यूड पॉइंट है जो गर्मी के मौसम में भी बर्फ से ढका रहता है। यहां पर आप स्नो स्कूटर से लेकर स्कीइंग और स्नोफॉल तक का लुत्फ उठा सकते हैं।

युमथांग वैली करें एक्सप्लोर

भारतीय राज्य सिक्किम में गंगटोक से तकरीबन 124 किलोमीटर दूर युमथांग वैली भी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको गर्मियों में भी बर्फ देखने को मिल जाएगी।"वैली ऑफ फ्लावर्स" के नाम से भी जाना जाता है।यहां के जीरो पॉइंट पर पूरे साल बर्फ देखने को मिल जाती है। यहां जाने के लिए आपको परमिट लेने की आवश्यकता होती है।

गर्मियों के दौरान क्यों अस्थिर हो जाता है शक्कर का स्तर? जानिए इसके 5 कारण

गर्मी का मौसम मधुमेह रोगियों के लिए चुनौतियों से भरा होता है। इस दौरान न केवल शक्कर के स्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, बल्कि शरीर में इंसुलिन का असर भी कम हो सकता है। इंसुलिन का असर कम होने से शरीर की कोशिकाएं शक्कर को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। आइए गर्मी के मौसम में शक्कर के स्तर में उतार-चढ़ाव आने के संभावित कारणों पर नजर डालते हैं।

खाने की आदतें

गर्मी के मौसम में खाने की आदतें भी प्रभावित हो सकती हैं। कई लोग ठंडे पेय और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं होते हैं। इससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है और इंसुलिन का असर कम हो सकता है। इसलिए, इस मौसम में पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लें और जंक फूड से दूर रहें।

भोजन का पाचन

गर्मियों के दौरान पाचन तंत्र की गति धीमी हो सकती है, जिससे भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता है। इससे शरीर में गैस, सूजन और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके कारण इंसुलिन का असर कम हो सकता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं शक्कर को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इससे शक्कर का स्तर अस्थिर हो सकता है और मधुमेह के लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं।

पानी की कमी

गर्मी के मौसम में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे इंसुलिन का असर कम हो जाता है और शक्कर का स्तर अस्थिर हो सकता है। इसके कारण मधुमेह रोगियों को थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, इस मौसम में अधिक से अधिक पानी पीएं और तरल पदार्थों का सेवन करें। साथ ही नमक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

इसके अलावा समय-समय पर अपने शक्कर के स्तर की जांच करवाते रहें।

व्यायाम की कमी

गर्मी से बचने के लिए कई लोग घर से बाहर नहीं निकलते और व्यायाम नहीं करते हैं, जिससे वजन बढ़ने लगता है। बढ़ता वजन इंसुलिन का असर कम कर सकता है। इसलिए, मधुमेह रोगियों को रोजाना कुछ मिनट व्यायाम जरूर करना चाहिए। इससे उनका वजन नियंत्रित रहेगा और मधुमेह के लक्षण भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा व्यायाम से शरीर में शक्कर का सही तरीके से अवशोषण हो सकता है।

तनाव और अनिद्रा

तनाव और अनिद्रा भी शक्कर के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। तनाव से शरीर में एक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे इंसुलिन का असर कम हो सकता है। वहीं अनिद्रा से शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता और शक्कर का स्तर अस्थिर हो सकता है। इसलिए, मधुमेह रोगियों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और तनाव को कम करने के उपाय अपनाने चाहिए। इनकी मदद से आप शक्कर के स्तर को स्थिर रख सकते हैं।

कहीं आपकी रोजाना की ये 5 आदतें आपको तनावग्रस्त तो नहीं बना रहीं

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी दिनचर्या सामान्य है, लेकिन कई बार छोटी-छोटी आदतें भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही आदतों पर चर्चा करेंगे, जो बिना जाने हमारी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती हैं। इन आदतों को पहचानकर और सुधारकर हम अपने जीवन को अधिक सुखद बना सकते हैं।

मोबाइल का अधिक उपयोग

मोबाइल का अधिक उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। जब हम लगातार अपने फोन पर नजरें गड़ाए रखते हैं तो इससे हमारी आंखों पर दबाव पड़ता है और नींद भी प्रभावित होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट देखने से भी तनाव बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि सोने से एक घंटा पहले और उठते ही एक घंटा मोबाइल का उपयोग न करें।

समय की कमी

समय की कमी भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अगर हम अपने कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाते तो इससे तनाव बढ़ता है। इसके अलावा समय पर आराम न करने से भी मानसिक थकान होती है। इससे बचने के लिए अपने दिनचर्या में समय प्रबंधन शामिल करें। कामों को प्राथमिकता दें और ब्रेक लें, ताकि आप तरोताजा महसूस करें और बेहतर तरीके से काम कर सकें।

चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन

चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन करने से हमारी नींद प्रभावित होती है और लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते। कैफीन युक्त चीजों का ज्यादा सेवन करने से हमारा शरीर तनावग्रस्त रहता है। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि दिनभर में एक-2 कप ही चाय या कॉफी का सेवन करें। अगर आप कैफीन युक्त चीजों का सेवन कम करेंगे तो इससे आपकी नींद बेहतर होगी और आप अधिक तरोताजा महसूस करेंगे।

सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि पर ज्यादा समय बिताने से हम दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कम होता जाता है। इससे बचने के लिए अपने सोशल मीडिया के उपयोग समय को सीमित करें और असली दुनिया के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करें। इसके अलावा अपनी सोशल मीडिया फीड को सकारात्मक और प्रेरणादायक चीजों से भरें, ताकि आपका मनोबल बढ़े और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें।

एक साथ कई काम करना

एक साथ कई काम करना भले ही आपको प्रभावी लगे, लेकिन यह आपके दिमाग पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे आप जल्दी थक जाते हैं। इससे बचने के लिए एक समय पर एक ही काम करें और उसे पूरा करने के बाद ही अगले काम पर जाएं। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इस तरह आप अधिक उत्पादक बन सकते हैं और तनावमुक्त रह सकते हैं।

रुपए की गिरावट को थामेगा $138 अरब का 'महाकवच'! भारत का ये धांसू हथियार बनेगा करेंसी का तारणहार

डॉलर के सामने रुपया 96।47 के लेवल के साथ लाइफ टाइम लोअर लेवल पर पहुंच गया है। हालात यही रहे तो साल खत्म होने से डॉलर के सामने रुपया 100 के आंकड़े को छू लेगा। वहीं दूसरी ओर तेल की कीमतों से पैदा हुआ दबाव चालू खाता घाटे को वित्त वर्ष 2026 के 0।9 फीसदी से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2027 तक जीडीपी के अनुमानित 2।3 फीसदी तक पहुंचाने की धमकी दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालने के लिए कौन सी तरकीब निकाली जाए। आरबीआई भी रुपए को संभालने के लिए कई हजार करोड़ रुपए के डॉलर की शॉर्ट सेलिंग कर चुका है।

वहीं जानकारों की मानें तो भारत के सामने रास्ते अभी बंद नहीं हुए है। भारत एक ऐसे एक्सपोर्ट की ओर देख रहा है, जो ना सिर्फ भारतीय करेंसी को डूबने से बचा सकता है। बल्कि कैड को भी कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है। वो एक्सपोर्ट है देश के लोगों का है। सरकार इसी की सक्रिय रूप से योजना बना रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से इजराइल के लिए कुशल श्रमिकों की तैनाती को सुरक्षित सरकारी-से-सरकारी माध्यमों से तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहा है।

1 करोड़ का टर्म प्लान @ ₹512/म*

तैनाती की समय-सीमा को व्यवस्थित रूप से कम करके और क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर बनाकर, भारत अपने विशाल डेमोग्राफिक डिविडेंड (demographic dividend) को एक प्रीमियम एक्सपोर्ट में बदलने का लक्ष्य रखा है। माइग्रेशन को बढ़ावा देने की यह रणनीतिक पहल, पूंजी-समृद्ध लेकिन श्रमिकों की कमी वाले देशों को बेहतरीन प्रतिभाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है, जिससे एक ऐसा मजबूत रेमिटेंस (remittance) सुरक्षा कवच तैयार होगा जो बड़े आर्थिक झटकों को झेलने में सक्षम होगा।

ग्लोबल लेबर मोबिलिटी की बदलती जियो पॉलिटिक्स

ग्लोबल माइग्रेशन के नक्शे में एक ढांचागत बदलाव आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी दुनिया के पारंपरिक गंतव्य देश अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्ती से सीमित कर रहे हैं। दशकों से, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप के कई देश भारत के कुशल प्रोफेशनल्स और छात्र प्रवासियों, दोनों के लिए मुख्य लक्ष्य रहे हैं।

हालांकि, अपने ही देश के लोगों को प्राथमिकता देने की बढ़ती भावना, लोकल पॉलिटिकल प्रेशर और वीजा नियमों की बढ़ती सख्ती, इंटरनेशनल लेबर फ्लो के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। पश्चिम में नियमों की इस सख्ती के कारण ह्यूमन रिसोर्स को नए रास्ते खोजने पड़ रहे हैं, जिससे एक ऐतिहासिक चुनौती अब एक विविध भू-राजनीतिक अवसर में बदल रही है।

खुशकिस्मती से, दुनिया के एक हिस्से में पहुंच कम होने के साथ ही, दूसरे हिस्से में इसके अवसर अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं रुकावटें खड़ी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ, बढ़ती उम्र की आबादी वाली और पूंजी-समृद्ध, लेकिन श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्थाएं अपने दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खोल रही हैं।

भारत इस व्यवस्थागत बदलाव का लाभ उठाने के लिए एक अनोखी स्थिति में है। वह प्रस्तावित 'ओवरसीज मोबिलिटी बिल' के जरिए अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आधुनिक बना सकता है। 1983 के पुराने 'इमिग्रेशन एक्ट' की जगह लेने के उद्देश्य से लाया गया यह नया बिल एक आधुनिक और व्यापक व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। यह व्यवस्था विदेशों में काम करने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षित रोजगार, उनके साथ उचित व्यवहार और देश वापसी पर उनके व्यवस्थित पुनर्वास को सुनिश्चित करती है।

सरकार की यह पहल इस बात की गारंटी देती है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव भारत के प्रतिभाशाली लोगों के विदेश जाने के रास्ते को अवरुद्ध न करे, बल्कि उन्हें ऐसे नए आर्थिक साझेदारों की ओर मोड़ दे जो केवल लेबर्स को इंपोर्ट करने के बजाय, मानव संसाधन के क्षेत्र में ढांचागत सहयोग को अधिक महत्व देते हैं।

इजराइल के लिए कॉरिडोर को तेज करना

इस बेहतर रणनीति का तुरंत फोकस पश्चिम एशिया है, जहां घरेलू चीजों की भारी कमी के कारण भरोसेमंद विदेशी कामगारों की तुरंत जरूरत पैदा हो गई है। फरवरी में तीन नए लागू करने वाले प्रोटोकॉल पर दोनों देशों के बीच दस्तखत होने के बाद, इजराइल ने अगले पांच सालों में 50,000 भारतीय कामगारों को अपने यहां काम देने का वादा किया है। भर्ती की यह वेव व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और रेस्टोरेंट जैसे जरूरी घरेलू सेक्टर्स तक फैली हुई है। इस मांग की वजह इस इलाके में आर्थिक रफ़्तार को बनाए रखने की जरूरत है, जिससे जांच-पड़ताल किए गए, काबिल लोगों का समय पर पहुंचना मेजबान देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है।

इस मांग को तेजी से पूरा करने के लिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने काबिल उम्मीदवारों की जांच-पड़ताल की सीधी जिम्मेदारी ले ली है, ताकि क्वालिटी पर सख्त कंट्रोल और नियमों का पालन पक्का किया जा सके। भर्ती के प्रोसेस को आसान बनाने पर भारत का जोर इसलिए है, ताकि उन सरकारी अड़चनों को दूर किया जा सके, जिन्होंने पहले भी सीमा पार रोजगार के रास्तों में रुकावटें पैदा की थीं।

इजराइल की आबादी और इमिग्रेशन अथॉरिटी के मुताबिक, देश में पहले से ही 48,881 भारतीय नागरिक रह रहे हैं। इस मौजूदा संख्या में 6,700 कंस्ट्रक्शन कामगार और 50 केयरगिवर शामिल हैं, जिन्हें सरकार-से-सरकार (G2G) चैनलों के जरिए सफलतापूर्वक भेजा गया है। लॉजिस्टिक्स में होने वाली देरी को कम करने के लिए विदेश मंत्रालय की जोरदार कोशिश यह दिखाती है कि भारत यह साबित करना चाहता है कि भारतीय कामगारों को भेजना बहुत तेज और पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है, जिससे भविष्य के बाइलेटरल लेबर कॉरिडोर के लिए एक मिसाल कायम होगी।

रूस और जापान में डेमोग्राफी की कमी का लाभ उठाना

पश्चिम एशिया से परे, भारत उन देशों के साथ गहरे और लंबे समय तक चलने वाले मानव पूंजी सहयोग स्थापित कर रहा है जो गंभीर और दीर्घकालिक डेमोग्राफिक संकटों का सामना कर रहे हैं। रूस तेजी से भारतीय तकनीकी और औद्योगिक प्रतिभा के लिए एक विशाल गंतव्य के रूप में उभर रहा है। रूसी श्रम मंत्रालय ने 2030 तक घरेलू कार्यबल में 3।1 मिलियन लोगों की भारी कमी का अनुमान लगाया है। अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को औद्योगिक उत्पादन बनाए रखने के लिए कम से कम 800,000 श्रमिकों की तत्काल आवश्यकता है। हालाँकि, कुछ क्षेत्रीय व्यापारिक नेताओं के शुरुआती अनुमान, जिनमें 1 मिलियन विशेषज्ञों के तत्काल आगमन की बात कही गई थी, कुछ ज्यादा ही आशावादी थे, लेकिन इसके लिए संरचनात्मक रास्ते अब काफी हद तक खुल रहे हैं।

इस विशाल अंतर को पाटने के लिए, रूस ने 2025 के लिए योग्य विदेशी विशेषज्ञों का अपना कोटा 1।5 गुना बढ़ाकर 230,000 कर दिया है, और एक अत्यंत स्पेसिफिक वीजा प्रोग्राम भी शुरू किया है। यह पहल कुशल विदेशी नागरिकों को बिना किसी कठोर भाषा की शर्त या कड़े स्थानीय कोटा के, तीन साल की अस्थायी या स्थायी नागरिकता प्रदान करती है। पिछले साल मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों ने भारतीय विशेषज्ञों के लिए रूस के IT, मशीनरी, निर्माण, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने का मार्ग प्रशस्त किया है।

इसके साथ ही, जापान भी अपने डेमोग्राफिक असंतुलन से निपटने के लिए इमिग्रेशन पर अपने पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी रुख में ढील दे रहा है। 'मानव संसाधन पर भारत-जापान कार्य योजना' एक बड़ी सफलता है, जिसका उद्देश्य पांच सालों की अवधि में 500,000 व्यक्तियों के आवागमन को सुगम बनाना है। इस लक्ष्य में 50,000 कुशल और अर्ध-कुशल भारतीय श्रमिक शामिल हैं। जापान अपने अत्यधिक दबाव वाले हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और देखभाल (caregiving) उद्योगों को बनाए रखने के लिए भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।

कॉर्पोरेट फुर्ती और टेक टैलेंट का डिसेंट्रलाइजेशन

पारंपरिक इमिग्रेशन प्रोसेस के सख्त होने से, मल्टीनेशनल टेक कंपनियां जिस तरह से बेहतरीन भारतीय टैलेंट को संभालती हैं, उसमें भी बदलाव आया है। पश्चिमी वीजा प्रोसेसिंग सिस्टम की अस्थिरता और लंबी देरी से जूझने के बजाय, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियां एक नए ऑपरेशनल थ्योरी के तहत अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बदल रही हैं — टीमें वहां बनाएं जहां टैलेंट पहले से मौजूद है। इंजीनियर को प्रोजेक्ट तक लाने के पुराने मॉडल की जगह अब डिसेंट्रलाइज हब ले रहे हैं, जो कंपनियों को बढ़ते संरक्षणवाद के बावजूद फुर्तीला बने रहने में मदद करते हैं।

यह रणनीति पिछले साल के IIT प्लेसमेंट साइकिल में साफ तौर पर दिखाई देती है। जहां IIT खड़गपुर जैसे प्रमुख संस्थानों में वीजा संबंधी अनिश्चितताओं के कारण अमेरिका स्थित कार्यालयों से सीधे नौकरी के प्रस्ताव शून्य रहे, वहीं इंटरनेशनल लेवल पर आई कुल गिरावट की भरपाई नीदरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और जापान से मिले हाई सैलरी वाले प्रस्तावों से हो गई।

इसके अलावा, सबसे ज्यादा सैलरी वाले पैकेज अब ज्यादातर उन भूमिकाओं के लिए दिए जा रहे हैं जो या तो भारत के भीतर ही हैं या फिर इन वैकल्पिक क्षेत्रीय हब में स्थित हैं। भूमिकाओं को लचीले भौगोलिक स्थानों पर ट्रांसफर करके, टेक्नोलॉजी कंपनियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि पश्चिमी राजनीतिक भावनाओं में आने वाले बदलावों के कारण बिना किसी रुकावट के उन्हें भारत के टॉप लेवल इंजीनियरिंग टैलेंट तक पहुंच मिलती रहे।

रेमिटेंस का सहारा

ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट में हो रही ढांचागत तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक जरूरी मैक्रोइकोनॉमिक सुरक्षा कवच देती है। जब रुपए पर लगातार नीचे जाने का दबाव होता है और वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण माल व्यापार घाटा घटता-बढ़ता रहता है, तो दुनिया भर में बसे भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई विदेशी करेंसी की आवक एक बेजोड़ वित्तीय मजबूती देती है। रेमिटेंस एक ऐसी मजबूत ताकत के तौर पर काम करता है जो इकोनॉमिक साइकिल के विपरीत चलती है। अक्सर घरेलू आर्थिक संकट के समय इसकी आवक बढ़ जाती है और यह लाखों परिवारों को तुरंत कैश मुहैया कराती है।

रुपए के कमजोर होने से विदेश में बसे भारतीयों को भारत में ज्यादा पैसे भेजने का प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इससे उन्हें बदले में ज्यादा रुपए मिलते हैं। भविष्य में विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगारों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने से, जब अचानक आए झटकों के कारण रुपया कमज़ोर पड़ेगा, तो उसे तुरंत सहारा मिल सकता है।

इकोनॉमिक सर्वे 202526 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत को रेमिटेंस के तौर पर 135।4 अरब डॉलर मिले, जिससे वह लगातार एक और साल दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बन गया। इसी दौरान, भारत में कुल FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की आवक लगभग 47 अरब डॉलर रही। विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगारों ने अपने घर लगभग तीन गुना ज़्यादा पैसे भेजे, जितना कि विदेशी निवेशकों ने भारत में निवेश किया था।

विदेशी पूंजी की यह भारी आवक ढांचागत रूप से झटकों को झेलने में सक्षम साबित हुई है। इसने लगातार भू-राजनीतिक संकटों, ऊर्जा की कीमतों में अचानक आई तेजी और बाहरी व्यापार में होने वाले उतार-चढ़ाव से भारत के 'बैलेंस ऑफ पेमेंट्स' (भुगतान संतुलन) को सुरक्षित रखा है। विदेशी संस्थागत निवेश (FII) के विपरीत—जो वैश्विक बाजारों में घबराहट फैलने पर तेजी से बाहर निकल सकता है—रेमिटेंस की आवक असाधारण रूप से स्थिर बनी रहती है। अपनी विशाल कामकाजी आबादी को एक औपचारिक, अत्यधिक संगठित और विश्व स्तर पर फैली हुई कार्यशक्ति में बदलकर, भारत सफलतापूर्वक केवल 'श्रम के निष्क्रिय सप्लायर' की भूमिका से आगे बढ़कर 'अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन नेटवर्क के रणनीतिक निर्माता' की भूमिका अपना सकता है। जिससे उसके 'करंट अकाउंट' (Current Account) के लिए दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।

7 साल बाद भारत आएंगे जिनपिंग? BRICS समिट में लेंगे हिस्सा, मोदी-पुतिन के साथ होगी मीटिंग

बीजिंग, एजेंसी। भारत इस साल सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों ने नई दिल्ली को इसकी जानकारी दे दी है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने पुतिन के भारत आने की बात की पुष्टि की है। क्रेमलिन के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक भी तय है। बता दें कि एक साल के भीतर यह पुतिन का दूसरा भारत दौर होगा। पुतिन ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। इस महीने की शुरुआत में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत आए थे। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स सदस्य देशों के दो दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सितंबर में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO का सम्मेलन होगा। वहां पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के शामिल होने की उम्मीद है।

बता दें कि भारत इस साल यानी 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। सितंबर में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

ब्रिक्स भारत समेत 11 देशों का समूह

ब्रिक्स दुनिया के 11 तेजी से बढ़ते देशों का एक बड़ा समूह है। इसमें भारत भी शामिल है। पहले इसमें केवल 5 देश (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) थे। साल 2024 में 4 नए देश जुड़े। इनमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE शामिल है। साल 2025 में इंडोनेशिया भी इस समूह का हिस्सा बन गया। यह समूह मिलकर दुनिया की लगभग 49। 5 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया की कुल कमाई यानी जीडीपी का लगभग 40 फीसदी और वैश्विक व्यापार का 26 फीसदी हिस्सा इन्हीं 11 देशों के पास है।

7 साल बाद जिनपिंग का भारत दौरा!

वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह भारत दौरा बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह करीब 7 साल बाद पहली बार भारत का दौरा करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2019 में भारत का दौरा किया था। उस समय वो चेन्नई के मामल्लापुरम आए थे।

ईरान से जंग को लेकर ट्रंप को अमेरिका में राहत और झटका दोनों

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ही समय में राजनीतिक झटका और राजनीतिक राहत दोनों देखने को मिले हैं। एक तरफ अमेरिकी सीनेट में युद्ध अधिकारों को लेकर ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राज्य केंटुकी (Kentucky) की राजनीति से ट्रंप को बड़ा सियासी संदेश मिला है कि रिपब्लिकन वोटर अभी भी उनके साथ खड़े हैं।

अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार(19 मई) को 50-47 के बहुमत से वॉर पावर्स रिजॉल्यूशन को आगे बढ़ा दिया। इस प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करना है ताकि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई जारी न रखी जा सके।

4 रिपब्लिकन सांसदों ने किया डेमोक्रेट्स का समर्थन

इस वोटिंग में चार रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेट्स का समर्थन किया। इसके कारण ट्रंप प्रशासन को राजनीतिक झटका लगा। हालांकि यह अभी अंतिम कानून नहीं बना है। इसे सीनेट में अंतिम मंजूरी, फिर रिपब्लिकन बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पारित होना होगा। इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप के पास वीटो का विकल्प मौजूद रहेगा।

क्या होगा ट्रंप प्रशासन का अगला कदम

ट्रंप प्रशासन के सामने एक और रास्ता यह भी हो सकता है कि सैन्य अभियान की कानूनी व्याख्या बदलने की कोशिश की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पहले भी कुछ सैन्य अभियानों को सीमित सैन्य कार्रवाई, रक्षा अभियान या श्रेणी में रखकर कानूनी समय सीमा और कांग्रेस के दबाव को संभालने की कोशिश की है। हालांकि नया नाम देकर किसी सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई जाती है या नहीं, यह ट्रंप प्रशासन के अगले कदम पर निर्भर करेगा।

केंटुकी से ट्रंप के लिए राहत की खबर

इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राहत की खबर केंटुकी से आई। ट्रंप और इजराइल समर्थक समूहों ने रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। थॉमस मैसी ईरान युद्ध, इजराइल नीति और कुछ संवेदनशील घरेलू मुद्दों पर ट्रंप से अलग लाइन लेते रहे थे।

केंटुकी में ट्रंप समर्थित उम्मीदवार की जीत को रिपब्लिकन राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इससे यह संदेश गया है कि रिपब्लिकन वोटर आधार अभी भी ट्रंप के साथ मजबूती से खड़ा है और पार्टी के भीतर ट्रंप की पकड़ बरकरार है।

अहमदीनेजाद पर दांव खेल रहे थे ट्रंप, एक हमले ने अमेरिका-इजराइल के ईरान प्लान को कर दिया ध्वस्त

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के मकसद से हमला कर वहां जोरदार तबाही मचाई, लेकिन सत्ता परिवर्तन में कामयाबी नहीं मिल सकी। फिलहाल दोनों ओर से संघर्ष विराम है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों की योजना ईरान में सत्ता पलट कर महमूद अहमदीनेजाद को ही गद्दी सौंपने का था। लेकिन एक हमले से पूरी योजना ध्वस्त हो गई। जबकि यह कहा जाता है कि अहमदीनेजाद भी इजराइल विरोधी रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से दावा किया गया है कि हमले के बाद अमेरिका और इजराइल की शुरुआती योजना ईरान पर सत्ता पलट कर अहमदीनेजाद को गद्दी सौंपने का था, लेकिन अहमदीनेजाद के घर पर हमले के बाद से वह पलट गए।

हालांकि अखबार के दावे के इतर अहमदीनेजाद की छवि इजराइल के कट्टर विरोधी के रूप में रही है, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के जरिए ईरानी सत्ता में प्रभावशाली लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है।

नजरबंदी से आजाद करने के लिए हमला!

अखबार लिखता है, "अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि तेहरान में अहमदीनेजाद को नजरबंदी से आजाद कराने के लिए किया गया एक हमला, देश में सत्ता परिवर्तन लाने और उन्हें सत्ता में बिठाने की कोशिश का ही एक हिस्सा था।" ईरान पर शुरुआती हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी और अन्य शीर्ष अधिकारियों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद, जो युद्ध की शुरुआती झड़पों का हिस्सा थे तब राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह विचार व्यक्त किया कि अच्छा यही होगा यदि ईरान के "अंदर से ही कोई" देश की बागडोर संभाल ले।

अब पता चला है कि अमेरिका और इजराइल इस जंग में बहुत ही चौंकाने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखकर ईरानी जंग में उतरे थे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद, जो अपने कट्टरपंथी तथा इजराइल-विरोधी और अमेरिका-विरोधी विचारों के लिए जाने जाते थे। लेकिन, अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, जिन्हें इस योजना के बारे में जानकारी दी गई थी, इजरायलियों की ओर से तैयार की यह साहसिक योजना (जिसके बारे में अहमदीनेजाद से भी चर्चा की गई थी) बहुत जल्द ही नाकाम हो गई।

हमले में घायल हुए तो प्लान से हट गए!

हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि तेहरान में अहमदीनेजाद को नजरबंदी से मुक्त कराने के मकसद से यह इजराइली हमला किया गया था। हमला सत्ता परिवर्तन करने और उन्हें सत्ता में बिठाने की कोशिश का ही एक हिस्सा था। अमेरिकी अधिकारियों और अहमदीनेजाद के एक सहयोगी ने बताया कि युद्ध शुरू होने के पहले ही दिन, तेहरान स्थित अहमदीनेजाद के घर पर एक इजरायल की ओर से हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। हालांकि इस हमले का मकसद उन्हें उनके 'नजरबंद' (House Arrest) की स्थिति से मुक्त कराना था। उन्होंने बताया कि अहमदीनेजाद इस हमले में बच तो गए, लेकिन बाल-बाल बचने के इस अनुभव के बाद, उनका 'सत्ता परिवर्तन' की इस योजना से मोहभंग हो गया और दूरी बना ली।

अभी कहां किसी को कुछ पता नहीं

इस हमले के बाद से उन्हें अब तक सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं देखा गया है, फिलहाल वह कहां हैं और किस हाल में हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

यह कहना कि अहमदीनेजाद का सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव एक "असामान्य" कदम था। असल में, इस बात के महत्व को बहुत कम करके आंका गया था क्योंकि शासन के नेताओं के साथ उनके टकराव लगातार बने हुए थे और ईरानी अधिकारियों ने उन पर कड़ी निगरानी रखी हुई थी। फिर भी 2005 से 2013 तक अपने राष्ट्रपतित्व काल के दौरान वह "इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने" के अपने आह्वान के लिए जाने जाते रहे थे। अहमदीनेजाद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रबल समर्थक थे, अमेरिका के कट्टर आलोचक थे, और आंतरिक असंतोष को कुचलने के लिए की जाने वाली हिंसक कार्रवाइयों के लिए भी वह खासे कुख्यात रहे थे।

प्लान में अहमदीनेजाद कैसे शामिल हुए?

हालांकि सत्ता परिवर्तन को लेकर अहमदीनेजाद को इस योजना में शामिल होने के लिए किस प्रकार राजी किया गया, यह बात अब भी एक रहस्य बनी हुई है। इस कोशिश का अस्तित्व- जिसके बारे में पहले कभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, इजरायल द्वारा ईरान की 'धर्म-आधारित सरकार' (Theocratic Government) को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार की गई एक बहु-चरणीय योजना का ही एक हिस्सा था।

यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न केवल गलत आकलन करते हुए इस युद्ध में उतर गए कि वे बहुत जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि उन्होंने ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की एक ऐसी जोखिम भरी योजना पर भी दांव लगाया, जिसे खुद ट्रंप के कुछ सहयोगी भी "असंभव" या "अविश्वसनीय" मानते थे।

आईसीएआर व एग्रोस्टार के बीच वैज्ञानिक कृषि और किसान सशक्तिकरण पर एमओयू

तकनीक आधारित कृषि, वैज्ञानिक परामर्श, फसल नवाचार और किसान क्षमता निर्माण पर रहेगा जोर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देशभर में वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के प्रसार, एआई-आधारित कृषि परामर्श सेवाओं के विस्तार तथा किसान क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत की अग्रणी एग्रीटेक कंपनी एग्रोस्टार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईसीएआर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत देश की सर्वोच्च कृषि अनुसंधान संस्था है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों के समन्वय एवं मार्गदर्शन का दायित्व निभाती है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आईसीएआर के महानिदेशक एवं सचिव डॉ. एम.एल. जाट ने की। आईसीएआर की ओर से उप महानिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने

पूसा परिसर/कृषि भवन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह साझेदारी विश्व के सबसे बड़े कृषि अनुसंधान नेटवर्क में से एक आईसीएआर तथा भारत के तेजी से उभरते किसान-केंद्रित एगटेक प्लेटफॉर्म एग्रोस्टार को एक साझा मंच पर लेकर आती है। आईसीएआर की शोध एवं विस्तार विशेषज्ञता और एग्रोस्टार के व्यापक डिजिटल किसान नेटवर्क के संयोजन से यह पहल कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल हानि में कमी, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, खेती की लागत में कमी तथा किसानों के लिए बेहतर बाजार अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगी। यह सहयोग एग्रोस्टार के मिशन "Helping Farmers Win" को और अधिक सशक्त बनाएगा।

समझौते के तहत एग्रोस्टार और आईसीएआर तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण, वैज्ञानिक फसल निदान प्रणाली, किसान परामर्श सेवाओं, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, फील्ड ट्रायल्स तथा कृषि प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक विस्तार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इसमें उन्नत फसल किस्मों एवं हाइब्रिड्स, जैविक नवाचारों तथा सूक्ष्मजीव-आधारित अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को मजबूती मिल सके।

इस सहयोग के माध्यम से किसानों को रियल-टाइम कृषि सलाह, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, उपग्रह एवं भू-स्थानिक विश्लेषण, एआई-संचालित फसल पूर्वानुमान, सटीक कृषि तकनीकों तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट्स तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। यह पहल पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और वैज्ञानिक फसल योजना जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी एवं डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता करेगी।

यह पहल एग्रोस्टार के एशिया के सबसे बड़े एग्री एडवाइजरी सेंटर तथा आईसीएआर के देशव्यापी अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों की संयुक्त विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी। आईसीएआर एवं केवीके के वैज्ञानिक फील्ड स्तर पर फसल निदान, किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का संचालन करेंगे, जबकि एग्रोस्टार अपने मजबूत जमीनी नेटवर्क के माध्यम से इन सेवाओं को किसानों तक अंतिम स्तर तक पहुँचाने का कार्य करेगा। यह साझेदारी भारतीय किसानों के बीच स्मार्ट कृषि उपकरणों, डिजिटल निर्णय सहायता प्रणालियों तथा सतत कृषि पद्धतियों के अपनाने को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस अवसर पर एग्रोस्टार के उपाध्यक्ष-अनुसंधान एवं नियामक मामलों, डॉ. देवराज आर्य ने कहा, "यह साझेदारी भारतीय किसानों के लिए वैज्ञानिक कृषि को अधिक सुलभ, व्यावहारिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आईसीएआर की शोध विशेषज्ञता और एग्रोस्टार की डिजिटल पहुंच एवं किसान सहभागिता तंत्र को एकीकृत कर हम ऐसे स्केलेबल और टिकाऊ समाधान विकसित करना चाहते हैं, जो कृषि उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और किसान आय को सुदृढ़ करने में सहायक हों।"

यह सहयोग भारत के कृषि विकास लक्ष्यों के अनुरूप तकनीक-आधारित, जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जमीनी स्तर पर वैज्ञानिक विशेषज्ञता, सटीक कृषि परामर्श और आधुनिक कृषि समाधानों तक पहुंच को मजबूत बनाकर यह पहल कृषि उत्पादकता, फसल गुणवत्ता, निर्यात क्षमता और दीर्घकालिक ग्रामीण समृद्धि को नई गति प्रदान करेगी।

एग्रोस्टार के बारे में

वर्ष 2013 में स्थापित एग्रोस्टार भारत की एक अग्रणी एगटेक कंपनी है, जो देशभर में लाखों किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी समाधान उपलब्ध करा रही है। कंपनी का ओमनीचैनल प्लेटफॉर्म 10,000 से अधिक रिटेल स्टोर्स के नेटवर्क के माध्यम से किसानों तक व्यापक कृषि सेवाएँ पहुँचाता है। एग्रोस्टार किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीयल-टाइम एग्रोनॉमी एडवाइजरी, गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट तथा वैश्विक बाजारों तक पहुँच जैसी समग्र कृषि समाधान सेवाएँ प्रदान करता है। कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो 200 से अधिक उत्पादों पर आधारित है, जिसमें सतत कृषि को बढ़ावा देने वाले समाधान शामिल हैं। इनमें जैविक विकल्प, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने वाले उत्पाद, मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाने वाले समाधान तथा उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज शामिल हैं।

पीएम मोदी की अपील का बिहार के मंत्रियों पर असर नहीं, शानो-ओ-शौकत में 10 से 15 गाड़ियों का काफिला

पटना, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर देश के लोगों से से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी, जिसके बाद तमाम नेताओं और सरकारों ने ईंधन बचाने के उपाय अपनाने शुरू कर दिए। किसी ने अपने काफिले में कमी की, तो कोई अपने ऑफिस इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचा, तो किसी ने ई-रिक्शा, मोटरसाइकिलों से यात्रा करना शुरू कर दिया है। वहीं कई ऑटो और साइकिल से यात्रा करते नजर आए। लेकिन बिहार से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर लगता है कि यहां के नेताओं पर पीएम की अपील का असर नहीं पड़ा। बिहार में नेता पीएम की ईंधन बचाने की अपील के बावजूद इसे नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। नेता गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम चंपारण से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां जिले में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन बेतिया पहुंचे।

फिल्म पेद्दी का ट्रेलर जारी, पहलवान बनकर दहाड़ने आए राम चरण, जाह्नवी कपूर छाईं

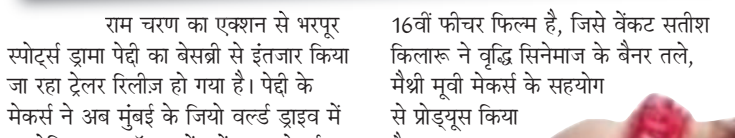

राम चरण का एक्शन से भरपूर स्पोर्ट्स ड्रामा पेद्दी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। पेद्दी के मेकर्स ने अब मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में आयोजित एक लॉन्च इवेंट में इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा का ट्रेलर पेश किया है। ट्रेलर में राम चरण दमदार अवतार में नजर आए है।

मेकर्स ने पेद्दी का ट्रेलर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है और कैप्शन में लिखा है, उसका अखाड़ा उसके नियम, उसका खेल अब शुरू होता है। पेद्दी का ट्रेलर अब आ गया है। पेद्दी 4 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में।

ट्रेलर की शुरुआत काफी दमदार हुई है। ट्रेलर की शुरुआत में राम चरण के किरदार का परिचय दिखाया गया है, जिसमें वह सबके फेवरेट क्रिकेटर, रनर और रेसलर होते हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे समय बदलता है, पर खिलाड़ी एक ही रहता है। पेद्दी, जिसका किरदार राम चरण निभा रहे हैं, के अंदर खेल को लेकर काफी जूनुन देखा जाता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे अपने हक की लड़ाई के लिए वह ऊंचे पद पर बैठे लोगों से लोहा लेता है।

राम चरण के फैंस इस फिल्म से जुड़ी किसी बड़ी अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि फिल्म की रिलीज में कई बार देरी हुई थी और रिलीज की तारीखें भी बदली थीं। रिलीज की तारीख में दो बार की देरी के बाद, फिल्म ने आखिरकार 4 जून को रिलीज की तारीख के तौर पर चुना।

बुची बाबू सना की निर्देशित, पेद्दी की कहानी 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश पर आधारित है। यह एक गांव वाले के सफर को दिखाती है, जो एक ताकतवर विरोधी के खिलाफ अपने गौरव की रक्षा के लिए खेल के जरिए अपने समुदाय को एकजुट करता है। इस फिल्म को एक एक्शन से भरपूर स्पोर्ट्स ड्रामा बताया जा रहा है, जिसमें मज़बूत भावनात्मक पहलू भी हैं।

मुख्य भूमिका में राम चरण के अलावा, इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। पेद्दी राम चरण की 16वीं फीचर फिल्म है, जिसे वेंकट सतीश किलारू ने वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले, मैथ्री मूवी मेकर्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है।

अगर पेड़ वाईफ़ाई देते ना, तो इंसान उन्हें रिचार्ज प्लान समझकर बचा के रखते : शहनाज़ गिल

एक्ट्रेस शहनाज़ गिल ने हाल ही में ट्री प्लांटेशन ड्राइव को सिर्फ इवेंट नहीं, इमोशन बना दिया। उन्होंने अपने दादा प्यारा सिंह की याद में एक पौधा लगाया — और इस छोटे से कदम में ढेर सारी मोहब्बत छुपी थी। दिल से बात करते हुए शहनाज़ ने ऐसा डायलॉग मारा जो सीधा दिल और दिमाग दोनों में सेव हो गयाः अगर पेड़ वाईफ़ाई दे रहा होता ना, तो कोई उसे काटता ही नहीं! लेकिन पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए सबको प्रॉब्लम है। फल खाओ, मजे से खाओज पर जड़ मत काटो। सुनो जी, ध्यान रखो - पेड़ लगाओ, बहुत जरूरी है! और

घरवालों को भी बोलोज जो दिनभर पड़ोसियों के साथ गॉसिप सम्मेलन करते हैं, वो मिलकर पेड़ लगाएं।

अपना आस-पास ठीक करो, एनवायरनमेंट खुद ही सेट हो जाएगा! अपनी सिग्नेचर देसी सच्चाई और फुल-ऑन रियल वाइब के साथ, शहनाज़ ने वो सच्चाई बोल दी जो हम सब जानते हैंज पर इग्नोर करते हैं। ऑक्सीजन फ्री है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं समझते — ये सीधा ताना भी था और मीठा रिमाइंडर भी।

उनकी बातों और इस प्यारे ट्रिब्यूट ने इस ड्राइव को सिर्फ पेड़ लगाने का प्रोग्राम नहीं रहने दिया, बल्कि एक ऐसा मैसेज बना दिया जो घर-घर तक पहुंचना चाहिए — बदलाव बड़ी स्पीच से नहीं, छोटे-छोटे कामों से शुरू होता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो शहनाज़ गिल जल्द ही इश्कनामा में नजर आने वाली हैं — और फैंस का एक्साइटमेंट तो पहले से ही फुल चार्ज है!

करुप्पू ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 दिन में बनाए चार रिकॉर्ड, बनी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

सूर्या की एक्शन ड्रामा फिल्म करुप्पू रिलीज होते ही छा गई है। फिल्म की सोशल मीडिया पर लोगों और क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी इसका जलवा देखने के लिए मिला। फिल्म की रिलीज को तीन दिन हुआ है और इसने ओपनिंग वीकेंड पर एक दो नहीं बल्कि चार रिकॉर्ड बना दिए हैं। ये फिल्म 2026 की तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बन चुकी है। ऐसे में चलिए बताते हैं कि इसकी वर्ल्डवाइड कमाई और रिकॉर्ड्स।

सूर्या की फिल्म करुप्पू ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है लेकिन वर्ल्डवाइड। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दो दिनों में 74 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद फिल्म को संडे की छुट्टी का फायदा मिला और इसकी कमाई वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के पार पहुंच गई है।

इसके साथ ही अगर फिल्म के इंडिया कलेक्शन के बारे में बात की

जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 15।50 करोड़, दूसरे दिन 24।15 करोड़ और तीसरे दिन रविवार को 28।35 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 68 करोड़ हो चुका है, जिसमें फिल्म ने तमिल में 57।70 करोड़ और 10।30 करोड़ का बिजनेस किया।

इतना ही नहीं, करुप्पू ने बॉक्स ऑफिस पर एक और रिकॉर्ड सेट किया। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का दो दिनों ग्रॉस कलेक्शन 74 करोड़ था। वहीं रविवार को बंपर उछाल मिली और फिल्म वर्ल्डवाइड 120।75 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। इसके साथ ही ये कोविड के बाद सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। सैकनिल्क के अनुसार, इसके पहले उनकी फिल्म कंगुवा ने 106 करोड़ वर्ल्डवाइड बिजनेस किया था।

इसके साथ ही करुप्पू ने साल 2026 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्मों को भी पछाड़ दिया है और ये अब 2026 की तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। जबकि दो दिनों की कमाई में ये 2026 चौथी तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई थी। लेकिन अब इसने पराशक्ति (84।75 करोड़ वर्ल्डवाइड) को पीछे छोड़ते हुए नंबर पर कब्जा कर लिया है।

इतना ही नहीं, सूर्या की फिल्म करुप्पू ने इंडिया में भी कमाल कर दिया है। महज दो भाषाओं तमिल और तेलुगु में रिलीज के बाद भी फिल्म ने इंडिया में ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। रविवार के के कलेक्शन के बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 68 करोड़ हो चुका है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com